वर्ष-4
अंक-19
रायपुर, शनिवार
31 अगस्त 2024
पृष्ठ-8
मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6>> होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं...

पैरा महिला शूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास

गोल्ड मेडल किए अपने नाम, मोना ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

नई दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक 2024 के दूसरे दिन भारत का खाता खुल गया है। भारत की झोली में एक साथ 2 मेडल आए हैं। जहां स्टार पैरा शूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल एसएच 1 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। वहीं, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एक ही इवेंट में 2 मेडल जीतकर भारत के पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार आगाज किया है।

इससे पहले अवनी लेखरा ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। अवनी क्वालीफिकेशन राउंड में 625.8 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान पर रहीं थी और पैरालंपिक रिकॉर्ड से चूक गई थी। उनका स्कोर पैरालंपिक रिकॉर्ड से केवल 0.2 प्वाइंट कम था। वहीं, मोना 623.1 के स्कोर के साथ पांचवें नंबर पर रहीं थी।

बता दें कि, अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली हैं और स्टार पैर शूटर हैं। अवनी पहली बार उस समय सुर्खियों में आई थी जब तीन साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में एसएच 1 कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का बड़ा कारनाम किया था। जबकि 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पेरिस में अब मेडल जीतने के साथ ही अब वह लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। 12 साल पहले अवनी का एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी।

इस चोट के चलते उनके शरीर के निचले हिस्से में पैरालिसिस हो गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा से प्रेरणा लेकर उन्होंने शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और अब लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया है। कार दुर्घटना में शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोट के बाद से अवनी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है। शूटिंग में एसएच1 श्रेणी में ऐसे निशानेबाज हिस्सा लेते हैं जिनकी बाहों, निचले धड़, पैरों की गति प्रभावित होती है या उनके हाथ या पैर में विकार होता है।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया मोना अग्रवाल को बधाई

पीएम मोदी ने मोना अग्रवाल के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 'एक्स' पोस्ट में लिखा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल एसएच 1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मोना अग्रवाल को बधाई! उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता की खोज को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। अवनि लेखरा ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ दो पदकों के साथ ही मौजूदा पैरालंपिक गेम्स में भारत का खाता भी खुल गया है।

भारत की बेटियां किसी से कम नहीं: साय

पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीत कर समूचे भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली महिला निशानेबाज अवनि लखेरा को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। मोना को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही यह भारत के लिए गर्व का क्षण है।

नतीजे के बजाय अपने विचारों पर ध्यान दे रही थी: लेखरा

ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा का ध्यान पेरिस पैरालंपिक में और अधिक पदक जीतने पर लगा है और उनका कहना है कि वह अपनी बची हुई दो स्पर्धाओं में भी पोडियम पर आना चाहती हैं। अवनि शुक्रवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) निशानेबाजी स्पर्धा लगातार दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं। तीन साल पहले तोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली 22 वर्षीय अवनि ने शानदार 249.7 अंक हासिल कर तीन साल पहले के अपने ही पैरालम्पिक रिकॉर्ड 249.6 को तोड़ दिया।

हिंदुत्व की राह पर हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी। लोकसभा चुनाव के बाद से देखें तो भाजपा शासित राज्यों के तीन मुख्यमंत्री एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं दूसरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके अलावा अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हिमंता बिस्वा सरमा भी लगातार हिंदुत्व की पिच पर तेजी से दौड़ रहे हैं। हाल के दिनों में हिमंता बिस्वा सरमा के बयान और काम कुछ ऐसे ही रहे हैं जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि वह कहीं ना कहीं आक्रामक हिंदुत्व की राह पर उतर चुके हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा सरमा के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने का धुन आज से नहीं है। भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। मुसलमानों के खिलाफ लगातार उनके बयान, इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने तथा जुम्मे की नमाज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि हिमंता हिंदुत्व की राह पर तेजी से दौड़ रहे हैं। आज ही असम विधानसभा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले दो घंटे के अवकाश को खत्म करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि 2 घंटे की जुम्मा छुट्टी को खत्म करके, असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और अवशेष को हटा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि

यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों को मेरा आभार। हिमंता बिस्वा सरमा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनमें ''मूलत- राज्य के निवासी हिंदू विधायकों'' को विधानसभा में अपनी बात नहीं रखने देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान, शर्मा ने अपनी पार्टी के विधायक भुवन पेगू के भाषण को बाधित करने के लिए भी विपक्षी सदस्यों की कड़ी आलोचना की। शर्मा ने पेगू का बचाव करते हुए कहा, मूलत- राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को सदन में नहीं बोलने देने की एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

मेरा यह समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है- चिराग पासवान

नई दिल्ली। बिहार में चिराग पासवान को लेकर एक अलग चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही यह भी दाहा किया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद भाजपा से संपर्क में हैं। कुल मिलाकर देखें तो चिराग पासवान जिस तरीके से हाल के दिनों में केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में खुलकर सामने आए हैं, उससे कई अटकलें का दौर शुरू हो गया है।

तरह-तरह के सियासी कयास लगाया जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है।

उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुझे को कोई अलग नहीं कर सकता है। चिराग पासवान स्पष्ट किया कि वह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि 'मेरा यह समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उन्होंने कहा कि जब मैं राजग का हिस्सा नहीं भी था तब भी मैं भाजपा और प्रधानमंत्री जी के विरोध में नहीं था। आज साथ में रहकर विरोध करने की सोच मेरी जेहन में कहीं से नहीं आ सकती है। युवा नेता ने कहा कि इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है। किस हद तक है, आप सभी ने उसे उस समय भी अनुभव किया होगा जब मैं अपने जीवन के सभी सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। तब भी मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर था और जितना स्नेह प्रधानमंत्री से मुझे मिला है, उसे आप लोगों ने हाजीपुर की सभा में उनके भाषण को सुना होगा।

चिराग पासवान ने कहा, ''इस बात को कहने में मुझे कभी कोई एतराज नहीं है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं, तबतक चिराग पासवान और प्रधानमंत्री दोंनो कभी अलग हो ही नहीं सकते। मेरा यह समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है।'' उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके विचार हमेशा सरकार के रुख को दर्शाते हैं.

कांग्रेस संगठन में नए सचिवों-संयुक्त सचिवों की नियुक्ति

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने कई नए सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं और कुछ राज्यों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में भी फेरबदल किया गया है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है। संगठन महासचिव के.सी.वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि ये पदाधिकारी पार्टी के महासचिव और संबंधित राज्यों के प्रभारियों के साथ काम करेंगे।

प्रणब झा और गौरव पांधी अब कांग्रेस के सचिव बनाए गए हैं। ये अब तक कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में समन्वयक थे। वहीं, विनीत पुनिया को कांग्रेस के संचार विभाग में सचिव बने रहेंगे। जबकि रुचिका चतुर्वेदी को इस विभाग में सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। राजस्थान के पूर्व विधायक दानिश अबरार को दिल्ली और दिव्या मदेरणा को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष नेट्टा डी सूजा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष नीरज कुंदन और नवीन शर्मा भी कांग्रेस के सचिव के रूप में काम करेंगे। साथ ही वेणुगोपाल भी इस भूमिका में रहेंगे। मनोज त्यागी और सुशांत मिश्रा को संयुक्त सचिव नियुक्ति किया गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि संगठन में वफादार और मेहनत करने वालों को इस फेरबदल के जरिए इनाम दिया गया है।

प्रमुख समाचार

कच्छ और पाकिस्तान में कहर बरपाएगा असना

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कारण बना गहरा दबाव शुक्रवार को कच्छ के तट और पाकिस्तान के आस-पास के इलाकों में चक्रवात असना में बदल गया। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में यह पहला चक्रवाती तूफान है। जिसे असना नाम पाकिस्तान ने दिया है। आईएमडी के अनुसार, 1891 से 2023 के बीच अगस्त के दौरान अरब सागर में केवल तीन चक्रवाती तूफान आए (1976, 1964 और 1944 में)। 1976 का चक्रवात ओडिशा से शुरू हुआ, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा, अरब सागर में प्रवेश किया, एक लूपिंग ट्रैक का अनुसरण किया और ओमान तट के पास उत्तर-पश्चिम अरब सागर में कमजोर पड़ गया। 1944 का चक्रवात अरब सागर में उभरने के बाद कमजोर पड़ने से पहले तेज हो गया था। 1964 में, दक्षिण गुजरात तट के पास एक और अल्पकालिक चक्रवात विकसित हुआ और तट के पास कमजोर पड़ गया। आईएमडी ने कहा कि कच्छ तट और पाकिस्तान के आस-पास के इलाकों और पूर्वोत्तर अरब सागर पर बना गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के वसूली एजेंट को बताया गुंडों का समूह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैंक की रिकवरी एजेंट फर्म को गुंडों का समूह करार देते हुए कहा कि उसने लोन की राशि के एकमुश्त निपटान के बावजूद एक व्यक्ति से जब्त वाहन वापस नहीं किया। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दो महीने के भीतर कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कोलकाता में बस चलाने के लिए 15.15 लाख रुपये का लोन लेने वाले देबाशीष बोसु रॉय चौधरी को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। मामले में पीठ ने बैंक ऑफ इंडिया को रिकवरी एजेंट से राशि वसूलने का निर्देश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, उच्च न्यायालय की तरफ से की गई टिप्पणियों और याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए तर्क को देखते हुए, हम देखा हैं कि प्रतिवादी संख्या 4, एक रिकवरी एजेंट, वास्तव में गुंडों का एक समूह प्रतीत होता है, जो याचिकाकर्ता-बैंक की ओर से लोन लेने वालों को परेशान करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है।

राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को भंग करने का अनुरोध

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद से भाजपा दिल्ली सरकार और उनकी पार्टी आप पर हमलावर है। इन सब के बीच भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और अनुरोध किया कि आप सरकार को भंग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने हमारी बात ध्यान से सुनी और वह हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन पर संज्ञान लेंगी। इससे पहले भाजपा ने कहा था कि आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के मद्देनजर दिल्ली में 'संवैधानिक संकट' का मुद्दा उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता गुप्ता ने कहा कि भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने और विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट पेश न करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

डॉक्टर के साथ बलात्कार पर सिब्बल का शर्मनाक बयान

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बात से स्तब्ध, दुखी और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हैं कि एक संसद सदस्य ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को लक्षणात्मक अस्वस्थता करार दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से सिब्बल ने कथित तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए भयावह बलात्कार और हत्या को लक्षणात्मक अस्वस्थता बताया गया था और सुझाव दिया गया था कि ऐसी घटनाएं आम हैं। सिब्बल को इस साल की शुरुआत में मई में स्ष्टक्क का अध्यक्ष चुना गया था। कोई यह कैसे कह सकता है कि ऐसी घटनाएं आम हैं? कितनी शर्म की बात है! धनखड़ ने एक कार्यक्रम में बिना किसी का नाम लिए कहा कि ऐसे रुख की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह इतने ऊंचे पद के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन मुझे खुशी है कि बार के सदस्य हमारी लड़कियों और महिलाओं के समर्थन में आए हैं।

फरक्का बैराज गेट खोलने की विदेशी मीडिया रिपोर्ट भ्रामक

नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें फरक्का बैराज गेट खोलने के माध्यम से बांग्लादेश बाढ़ में उसकी संलिप्तता का सुझाव दिया गया था, यह कहते हुए कि यह रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच डेटा और महत्वपूर्ण सूचनाओं के नियमित और समय पर आदान-प्रदान को नजरअंदाज किया गया है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमने बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पर सीएनएन रिपोर्ट देखी है। इसकी कहानी भ्रामक है और सुझाव देती है कि बाढ़ के लिए भारत किसी तरह जिम्मेदार है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित तथ्यों को नजरअंदाज करता है। स्थिति। उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया है कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए मौजूदा संयुक्त तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी का नियमित और समय पर आदान-प्रदान होता है। सीएनएन की रिपोर्ट के बाद भारत की प्रतिक्रिया आई कि बांग्लादेश इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से गुजर रहा है - जिसमें कई जिले जलमग्न हो गए हैं और फेनी शहर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है.

हरियाणा की लाल विरासत में भाजपा की सेंध, एंटी-इनकम्बेंसी पर सवार कांग्रेस

जितेंद्र भारद्वाज

हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा, दोनों पार्टियों के बीच इस बार कांटे का मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है। भाजपा, प्रदेश के तीन %लाल% परिवार, यानी पूर्व सीएम चौ. देवीलाल, चौ. बंसीलाल और चौ. भजनलाल की विरासत संभालने वालों में सेंध लगा चुकी है। वर्तमान में इन तीनों ही परिवारों का कोई न कोई सदस्य %भाजपा% में शामिल हो चुका है। विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही परिवारों के सदस्यों की टिकट के लिए तगड़ी दावेदारी भी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी, भाजपा के 10 साल की एंटी-इनकम्बेंसी पर सवार है तो वहीं भाजपा %लाल% परिवारों पर भरोसा जता, चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव, बहुत रौचक होगा। अपनी जीत के प्रति भले ही दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं, मगर एंटी-इनकम्बेंसी के चलते भाजपा की राह कुछ मुश्किल होती दिखाई पड़ रही है।

हरियाणा में एक अक्तूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे, चार अक्तूबर को आएंगे। प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने चंद्रशेखर आजाद की %आजाद समाज पार्टी% (कांशीराम) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जजपा 70 सीटों पर तो आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनके अलावा इनेलो ने भी बसपा के साथ चुनावी गठबंधन किया है। कुछ सीटों को छोड़कर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा। भाजपा को उम्मीद है कि उसे %लाल% परिवारों की विरासत को संभालने वाले कुछ सदस्यों के साथ आने का फायदा मिलेगा। चौ. देवीलाल परिवार के सदस्य चौ. रणजीत सिंह चौटाला, भाजपा में हैं। वे हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री हैं। पार्टी ने उन्हें लोकसभा टिकट भी दिया था, मगर वे हार गए। अब चौटाला ने कहा है कि भाजपा उन्हें रानियां सीट से टिकट देती है, तो ठीक है, वरना भाजपा अपना देख ले।

प्रदेश की सियासत में रणजीत चौटाला के इस बयान ने भाजपा को असहज स्थिति में ला दिया है। प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले रविंद्र कुमार बताते हैं, भाजपा ने जब %लाल% परिवारों के सदस्यों को भगवा पटका पहनाया, तो उसके नेताओं को यह उम्मीद थी कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी की राह आसान हो जाएगी। दूसरा जाट वोट बैंक, जो भाजपा से पूरी तरह छिटक चुका है, उसके निकट आने की उम्मीद की गई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दस में से पांच सीटें खो दी हैं। पार्टी को जाट समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा। खुद रणजीत चौटाला, चुनाव हार गए। ऐसे में भाजपा को चौ. देवीलाल परिवार के सदस्य रणजीत सिंह चौटाला के आने का ज्यादा फायदा नहीं हुआ।

चौ. बंसीलाल परिवार से उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी ने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन कर ली थी। भाजपा कोटे से अब वे राज्यसभा में भी पहुंच गई हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट की मजबूत दावेदार हैं। भाजपा को उम्मीद है कि उसे भिवानी जिले की कुछ सीटों पर फायदा होगा। हालांकि इस बार प्रदेश में जिस तरह की टक्कर है, उसमें किसी दल को परिवार विशेष से कोई फायदा होगा, ऐसी गुंजाइश कम ही है।

तीसरा लाल परिवार चौ. भजनलाल का है। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हैं। उनका बेटा, भव्य बिश्नोई विधायक है। वे इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। राजनीतिक जानकार के मुताबिक, अब प्रदेश में ऐसा कोई %लाल% परिवार नहीं है, जिसका प्रभाव अधिकांश सीटों पर हो। ये राजनीतिक घराने अब कुछ ही सीटों तक सिमट गए हैं। रणजीत चौटाला और किरण चौधरी, भाजपा की बड़ी मदद कर पाएंगे, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। ये नेता विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जाट समुदाय के वोट खींच पाएंगे, ये आसान नहीं है। कुलदीप बिश्नोई परिवार भी करीब करीब अपनी ही सीट तक सीमित है। उनके भाई चंद्रमोहन कांग्रेस पार्टी में पंचकुला और कालका सीट तक ही सक्रिय हैं।

बतौर रविंद्र कुमार, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में भाजपा को जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा। भाजपा के लिए दस साल की एंटी-इनकम्बेंसी, कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। चुनाव से कुछ माह पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह नायब सैनी को ले आना, भाजपा को इसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। नतीजा, पार्टी को अपनी पहले वाली सोशल इंजीनियरिंग पर लौटना पड़ा है। जिस वर्ग यानी गैर जाटों को भाजपा अपना बताने का दावा करती है, उसकी संख्या करीब 75 फीसदी है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से जाट समुदाय का समर्थन हासिल किया है। जाट वोटों पर अपना हक जताने वाली इनेलो और जजपा, को नकार दिया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मौजूदा समय में एक मात्र जाट नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल जाट समुदाय का ही नहीं, बल्कि गैर जाट वोटरों का भी समर्थन हासिल था। विशेषकर एससी समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। दूसरे समुदाय के लोग भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। भाजपा ने जाट समुदाय के वोट हासिल करने के लिए तमाम प्रयास किए, मगर उसे समर्थन नहीं मिल

अब सरगुजा में नहीं होगा पेयजल संकट भारी बारिश से 33 फीसद भरा बांकी डैम

सरगुजा। सूखे के संकट से जूझ रहे सरगुजा में बारिश ने रिकार्ड तोड़ दिया है। अच्छी बारिश के कारण शहर के बांकी जलाशय में जलभराव होने से जल संकट से मुक्ती मिल सकेगी। आने वाले समय में नगर निगम क्षेत्र में होने वाले पेय जल की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि पिछले 7 सालों से बांकी जलाशय का जल स्तर बेहद नीचे था। पिछले साल बांकी डैम सूखने की कगार पर था। यही कारण है कि भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराया थे, लेकिन इस बार की बारिश ने सूखे की चिंता दूर कर दी है।

दरअसल, अम्बिकापुर शहर के लिए जीवनदायनी बांकी परियोजना में हुआ जल भराव का नजारा सालों बाद देखने को मिला है। साल 1990 में बनी इस परियोजना से आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था। ये डेम अंबिकापुर शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए जीवनदायिनी है। साल 2017 में ये बांध पूरी तरह से लबालब था। हालांकि पिछले 7 सालों में इस बांध में पानी का संकट है। आलम ये है कि बीते गर्मी में बांध के सूख जाने के कारण शहर में पेयजल की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही थी।

हालांकि, इस बार डैम में अब तक 33 फीसद जल भराव हो चुका है। जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि इस बार डैम 50 फीसद के करीब भरेगा, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही बचे पानी से सिंचाई भी हो सकेगी।

इस बारे में जल संसाधन विभाग के ईई अशोक निरंजन ने कहा, बांकी परियोजना हमारी प्रमुख परियोजना है। इससे ही शहर में पेयजल की सप्लाई की जाती है। साल 2018 में इसमें जल स्तर काफी कम हो गया था, लेकिन अभी इस साल अच्छी वर्षा हुई है। इससे डैम में 33 फीसद पानी भर गया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस मानसून में डैम 50 फीसद भर जाएगा, जिससे आराम से शहर को जल आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही बचे हुए जल को सिंचाई के लिए भी दिया जा सकेगा।

मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने कहा इस वर्षा आंकड़े के साथ अगस्त माह में कुल वर्षा 548.3 मिमी से अधिक हो चुकी है। 1 जून से 25 अगस्त तक कुल वर्षा 1033.9 मिमी से अधिक हुई है। अगस्त माह में वर्षा के उपलब्ध रिकॉर्ड 1969 से 2024 के बीच है। इस साल अगस्त में अभी तक तीसरी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसके पहले पूरे अगस्त में साल 1991 में 642.4 मिमी और साल 2016 में 698.2 मिमी की रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई थी। ये वर्षा सामान्य है, लेकिन इससे कृषि और आस पास के जलाशय, डैम और तालाबों में जल की स्थिति अच्छी हो गई है।

सरगुजा में शुरुआत में मानसून ने धोखा दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि सरगुजा सूखे की चपेट में है। लेकिन अगस्त माह में हुई अच्छी बारिश ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त माह में हुई बारिश ने 56 सालों में तीसरी सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिक की मानें तो आने वाले दिनों में भी सरगुजा में बेहतर बारिश होगी, जिससे पानी की कमी पूरी हो सकेगी।

बालोद में बोले मंत्री लखन लाल देवांगन

भाजपा में हूं तो मंत्री बन पाया कांग्रेस में संभव नहीं होता

बालोद। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन बालोद में आयोजित देवांगन समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान शहर के दल्ली चौक पर भाजपा पदाधिकारी और समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली के जरिए कार्यकर्ता उन्हें आयोजन स्थल टाउन हॉल तक लेकर आए।

इस दौरान मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज संगठित रहे। जो बिखरा हुआ है, उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास होना चाहिए। रोटी-बेटी का संबंध भी एक साथ बनना चाहिए। भाजपा में हूं तो मंत्री बन पाया, कांग्रेस में ये संभव नहीं था।मैं कांग्रेस में होता तो आज मंत्री ना बन पाता। कोरबा में जनबल ने धनबल को ठुकरा कर मुझे मौका दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत सीधे और सरल हैं। कांग्रेस लाठीचार्ज पर आज प्रदर्शन की, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगी। भाजपा

की सरकार बिना भेदभाव के काम करती है।

लखन लाल देवांगन ने कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। इस सरकार में जनता के हित में काम हो रहा है। भाजपा का भविष्य उज्ज्वल है। कांग्रेस में छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाता है।

इस दौरान देवांगन समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक देवांगन ने कहा, देवांगन समाज का मैं कार्यकर्ता हूं। आप सबने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। समाज हमें काफी कुछ सीखने का मौका देती है। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करूंगा। शासन की ओर से समाज के भवन के बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

भाजपा जिलाध्यक्ष पवन साहू, ने कहा हम समाज के लोग हैं। हम सबकी सहभागिता से समाज बनता है। कुछ लोगों ने हमारे समाज, हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को खंडित करने का काम किया जाता है। इनसे हमें बचकर रहना है। लखन लाल जी के नेतृत्व में समाज के हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए काम करना है।

बता दें कि देवांगन समाज के इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, पोषण लाल देवांगन, बालोद ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण देवांगन सहित अन्य सामाजित कार्यकर्ता मौजूद थे।

एकलव्य विद्यालय के 40 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार

अधिकारियों में मचा हड़कंप

जगदलपुर। जगदलपुर धरमपुरा स्थित एकलव्य विद्यायल में बीती रात बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसके बाद सभी बच्चों को महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, शुक्रवार की सुबह भी कई बच्चे बीमार हो गए। करीब 40 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी लगते ही सहायक आयुक्त की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि एकलव्य विद्यालय धरमपुरा में छठी से 10वीं तक के करीब 300 बच्चे पढ़ते हैं। बीती रात सभी बच्चे खाना खाने के बाद सो गए। रात करीब 12 बजे के बाद बच्चों को उल्टी होना शुरू हो गई। जिसके बाद अन्य साथियों ने इसकी जानकारी अधीक्षक को दी। जिसके बाद चार वाहन 108 की मौके पर पहुंचे। बच्चों का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि वे बेहोश तक हो गए। रात को करीब 25 बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से महारानी अस्पताल लाया गया, जबकि अन्य बच्चों को शुक्रवार की सुबह फिर से चार वाहनों की मदद से महारानी लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है।

इस मामले में सहायक आयुक्त गणेश सोरी का कहना था कि मामले की जानकारी लगते ही टीम पहुंच गई। जहां खाने की सामान की जांच की जा रही है। साथ ही वहां की स्थिति को भी देखा जा रहा है। इसके अलावा बच्चों से भी बात की जा रही है कि आखिर किन कारणों के चलते अचानक से बच्चो को उल्टियां होनी शुरू हो गई। फिलहाल बच्चों का उपचार जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 40 बच्चे है जिनका उपचार चल रहा है।

मनेंद्रगढ़ में घूम रहा 11 हाथियों का दल, दहशत में ग्रामीण

एलीफेंट्स पर वन विभाग की नजर

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। वन मण्डल मनेंद्रगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। जिससे इलाके में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है।

दहियाडाँड़ के पंडरा नाला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह इन हाथियों के दल को देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 11 हाथियों का दल बीट दहियाडाड़ के कक्ष क्रमांक क्रम 962 में घूम रहा है। यह दल संभावित रूप से ग्राम चनवारीडाड़, दहियाडाड़, शिवपुर, डिहुली, मुड़धोवा और देवरा की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी है।

वन परिक्षेत्राधिकारी रामसागर कुर्रे ने बताया हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है। हाथी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहां के गांव वालों को पहले से सूचना दी जा रही है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे जंगल की ओर न जाएं और खुद को सुरक्षित रखें। शाम के समय घर से बाहर ना निकलें।

11 हाथियों के दल ने अब तक किसी भी तरह की जनहानि या फसल नुकसान नहीं किया है। लेकिन हाथियों का यह दल किसी भी समय खतरनाक साबित हो सकता है। जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। मानसून के इस मौसम में ग्रामीणों का जंगल और खेतों की ओर जाना आम है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है।

भरतपुर में डौकीझरिया व्यपर्वतन योजना के तहत बना बांध टूटा, अन्नदाता परेशान

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। वनांचल क्षेत्र भरतपुर के चुटकी गांव में डौकीझरिया व्यपर्वतन योजना के तहत बना बांध धराशायी हो गया है। करोड़ों की लागत से बना बांध पहली बारिश में ही टूट गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

ग्रामीणों की मानें तो ग्राम चुटकी में बनाए गए स्टॉप डैम से किसानों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। यह डैम खेतों के लिए जीवनरेखा बन सकता था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि पहली बारिश में ही यह बांध ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के सपने बिखर गए हैं।

किसान सुंदरलाल मिश्रा ने कहा पहले ही आषाढ़ में यह बांध टूट कर बह गया। जहां कच्चा था, वहां शुरुआत में ही टूट गया था। जहां पक्का था, वह

अब टूट गया है। आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। एक बार किसी तरह बांधकर पानी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर सुबह टूट गया।

चुटकी गांव के सरपंच राम नारायण बैगा ने कहा, बांध के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण बांध का सही ढंग से निर्माण नहीं हो सका। इस कारण शुरुआती बारिश में ही ये धाराशाई हो गया। इस बारे में ठेकेदार विनीत सिंह ने कहा, इस बांध में 10 साल की गारंटी है। हम इसकी रिपेयरिंग का काम कराते रहेंगे।

वहीं, ग्रामीणों का कहना है, बांध में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदार ने घटिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि बांध पहली बारिश में ही टूट गया। वहीं भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी।

विधायक रेणुका सिंह ने कहा ये गलत है। इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी जांच की जाएगी।

चुटकी गांव में डौकीझरिया व्यपर्वतन योजना के तहत बनी बांध के टूटने से जहां एक ओर ग्रामीणों और किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं, दूसरी ओर ठेकेदार वापस रिपेयरिंग की बात कह रहे हैं। इसे लेकर गांव के सरपंच ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं, विधायक रेणुका सिंह ने जांच का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पीकेईबी कोल परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई शुरू

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले स्थित उदयपुर अंतर्गत परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना फेस 2 के लिए आज शुक्रवार को प्रभावित ग्राम पहुंचकर पेड़ो की कटाई प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कराई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। कोल खदान के लिए पेड़ों की कटाई प्रभावित ग्राम सालही, घाटबर्रा, हरिहरपुर व फतेहपुर के सैकड़ों महिला-पुरुषों द्वारा जंगल में घुसकर रात से ही पहरा दिया जा रहा। मौके पर विरोध कर रहे दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आंदोलनकारियों को बसों में भरकर उदयपुर और लखनपुर थाना भेज दिया गया है। वनविभाग के अनुसार फेस 2 के लिए 11 हजार पेड़ों की कटाई होनी है। ग्रामीण हसदेव को बचाने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व प्रशासन ने गत वर्ष 8000 पेड़ों की कटाई कराई थी। पीकेईबी खदान के पेड़ों को काटने की सहमति पूर्व में दी जा चुकी है। पीकेईबी खदान राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का आबंटित है, जिसका एमडीओ अदानी इंटरप्राइजेस है।

सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की हेराफेरी

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के सरकारी राशन दुकान में 42 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले में दो दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने जांच की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सरकंडा पुलिस ने हेराफेरी करने वाले दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ियों को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इसी कड़ी में खाद्य निरीक्षकों ने मुक्तिधाम चौक सरकंडा में संचालित राशन दुकान की जांच की। अजय मिश्रा द्वारा संचालित राशन दुकान आईडी क्रमांक 401001070 में गड़बड़ी मिली, साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान बजरंग प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सरकंडा आईडी क्र. 401001083 के संचालक कैलाशनाथ मिश्रा के दुकान में भी गड़बड़ी पाई गई थी।

लकड़बग्घा शहर में घूमता दिखा, दहशत में लोग

नारायणपुर। प्रदेश के नारायणपुर जिला के बखरूपारा और आसपास के क्षेत्रों में लोग इन दिनों लकड़बग्घा के घूमने से काफी डरे हुए हैं। यह लकड़बग्घा हाल ही में वन विभाग के काष्ठागार डिपो, बखरूपारा में देखा गया है, जिससे स्थानीय निवासियों की चिंता और बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह लकड़बग्घे को फॉरेस्ट विभाग के काष्ठागार डिपो में घूमते हुए देखा गया। यह मामला और भी गंभीर हो जाती है जब इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी कहीं और व्यस्त हैं। ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों में लकड़बग्घे को लेकर दहशत का माहौल है। लेकिन वन विभाग अब तक इसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया है। नारायणपुर वन परिचेत्र अधिकारी इंद्र कुमार यादव ने बताया कि वे दो दिनों से रायपुर में वन विभाग की तरफ से आयोजित खेल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि नारायणपुर में वन अमले की टीम को लकड़बग्घा पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है।

बस्तर में धर्मांतरण का मामला कफन दफन को लेकर विवाद

जगदलपुर। बस्तर में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सामने आया है। बस्तर ब्लॉक के बाकेल गांव में धर्मांतरित परिवार में मृत्यु के बाद कफन दफन को लेकर विवाद की स्थिति बनी। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अमला पहुंचकर विवाद को शांत कराने की कोशिश में लगे हैं। बताया जा रहा कि मृत व्यक्ति विशेष धर्म का प्रचारक था। ग्रामीण मृतक परिवार को मूल धर्म में वापसी करने के बाद ही कफन दफन करने पर अड़े रहे। काफी विवाद के बीच धर्मांतरित परिवार मूल धर्म में वापसी को तैयार हुआ। पुलिस व ग्रामीणों के समक्ष धर्मांतरित परिवार मूल धर्म में वापसी का लिखित प्रतिवेदन दिया। इसके बाद मूल धर्म के रीति रिवाज के साथ पुजारी, नाईक, पाइक व ग्रामीणों ने वापसी करवाई। मूल धर्म में वापसी के बाद ग्रामसभा द्वारा गांव में अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी गई।

एनएमडीसी पर 1620 करोड़ रुपए का अर्थदंड

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएमडीसी किरंदुल को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर एनएमडीसी ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है।

पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी सर्वे पूरा करने के निर्देश

बलरामपुर रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं।जिसके लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने बलरामपुर जिले का दौरा किया। जहां आरएस विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस दौरान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने बलरामपुर जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने सभी विभागों के अफसरों को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए

निर्देश दिए।जिसमें लोगों की हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का इम्पलिटेशन करने को कहा।साथ ही साथ जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी रिव्यू मीटिंग भी ली।

आरएस विश्वकर्मा ने कहा जैसे राशनकार्ड बनाना है तो राशनकार्ड में पिछड़े वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। उज्जवला योजना है इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को कितने कनेक्शन दिए गए। टोटल कनेक्शन कितने दिए। वो हम लोग अनुपात चेक करते हैं। उसके अनुपात के हिसाब से आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इसकी समीक्षा हम लोग करते हैं।

इस दौरान छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण की हिस्सेदारी के कार्य को प्राथमिकता से समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।

गांव में खदान खोलने का विरोध जनसुनवाई में जमकर चले लात-घुसे

दुर्ग। जिले के ग्राम चुनकट्टा में लाइम स्टोन की खदान को लेकर हो रही पर्यावरण विभाग की जनसुनवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस दौरान जमकर लात घुसे भी चले। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण ही आपस में भिड़ गए। एक ग्रामीण का सिर भी फट गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद माहौल को शांत कराया। बता दें कि एडीएम अरविंद एक्का खदान को लेकर जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीण ही आपस में भिड़ गए। खदान से होने वाले पर्यावरण के नुकसान और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर असर को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। वहीं जनप्रतिनिधियों और आरटीआई कार्यकर्ता ने ग्रामीणों की सहमति के लिए खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक, चुनकट्टा में 1।58 हेक्टेयर जमीन पर खनन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए आज जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। एक ग्रामीण का सिर फट गया। तीन थानों के थाना प्रभारी और ट्रैफिक जवानों ने मोर्चा संभाला।

'अधिकारियों के दबाव में लगाई अपहरण की धारा'

एसआई के जवाब से हैरान हुईं न्यायाधीश, आईजी-एसपी को दिया कड़ा संदेश

दुर्ग। जिम संचालक अमित लखवानी के अपहरण और मारपीट के मामले गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूरे प्रकरण में भिलाई 3 थाना के एसआई ने जिस तरह से तर्क दिए उसने न्यायाधीश को हैरान कर दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी को फिर से जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता

पर लगाई गई अपहरण की धारा पर महिला न्यायाधीश ने सवाल किया, तब एसआई वर्मा पहले पहल तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा लगाने की बात कही।

महिला न्यायधीश ने एसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको जानकारी है कि दबाव में धारा लगाने पर नौकरी भी जा सकती है। जिसके बाद नजरुल इस्माइल को जमानत देते हुए। दुर्ग एसपी और आईजी को इस मामले में फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिम संचालक अमित लखवानी को जिम से उठाकर थाने में लाने और मारपीट के मामले में पुलिस चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य पार्षदों की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सभापति कृष्णा दो अन्य पार्षद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने में लगे हुए हैं, फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं।

'कृषि अवसंरचना कोष' के विस्तार को मंज़ूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'कृषि अवसंरचना कोष' के विस्तार को मंज़ूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हाल ही में केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'कृषि अवसंरचना कोष' के विस्तार को मंज़ूरी दी है, जिससे कृषि परियोजनाओं को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है, जो देश और प्रदेश दोनों में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास में सहायक होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि उत्पादन में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम मोदी सरकार की कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उद्योग मंत्री आज मुंगेली में जिला अधिकारियों की लेंगे बैठक

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री तथा मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन शनिवार 31 अगस्त को मुंगेली जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री श्री देवांगन 31 अगस्त को 11 बजे रायपुर से मुंगेली जिला के लिए कार द्वारा प्रस्थान करेंगे। एक बजे विश्राम भवन मुंगेली आगमन जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद अपरान्ह 3 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेंगे। तत्पश्चात श्री देवांगन 4.30 बजे मुंगेली से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

टीआई लाइन अटैच, 3 पुलिसकर्मी निलंबित

रायपुर। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने गंभीर मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीआई-मुंशी तथा अवैध शराब बिकवाने के आरोपी आरक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। बताते हैं, विधानसभा के एक कर्मचारी ने दो दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। इसमें विधानसभा थाने के टीआई मुकेश शर्मा ने इसकी विवेचना में लापरवाही बरती। इस पर एसएसपी संतोष सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए आज दोपहर लाइन हाजिर कर दिया। वहीं, थाने के मुंशी को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी की इस कार्रवाई से रायपुर पुलिस में हड़कंप मच गया है। बहरहाल, एसएसपी ने रक्षित निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह को विधानसभा थाने का नया टीआई नियुक्त किया है। उधर, अवैध शराब का धंधा करने वाले दो सिपाहियों पर भी एसएसपी की गाज गिरी है। पुरानी बस्ती के दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताते हैं, थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत संचालित डॉयल 112 वाहन के टाइगर 2 में तैनात आरक्षक 2637 प्रताप ओगरे थाना पुरानीबस्ती एवं टाइगर 3 में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1917 प्रमेश देवांगन के द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्धारित वर्दी धारण किये हुये, अवैध शराब बिक्री में संदिग्ध संलिप्तता व आचरण प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों आरक्षकों को एसपी ने निलंबित कर दिया।

काम में ढिलाई बरतने पर तीन तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस

बिलासपुर। न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर तीन नायब तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिल्हा तहसील के नायब तहसीलदार श्री लखेश्वर किरण, विनीता शर्मा और पचपेड़ी के नायब तहसीलदार श्री अभिराम पाण्डेय शामिल है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एडीएम श्री आर.ए. कुरुवंशी ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ गिरदावरी का कार्य 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार के प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। विशेषकर 6 माह एवं 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाए। स्वामित्व योजना अंतर्गत मिले नक्शों का सत्यापन कर एक सप्ताह में प्रेषित करने कहा गया। उन्होंने कहा कि इस खरीफ वर्ष में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम शुरू किया गया है जिसमें बोदरी तहसील के अंतर्गत सभी हल्कों में यह काम किया जाए। इसके अलावा सभी तहसील के दो-दो गांवों में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण का कार्य जल्द करने कहा गया।

रेत के अवैध परिवहन पर ग्रामीणों की कार्रवाई के बाद जागे अधिकारी

नवापारा राजिम। रायपुर जिला अंतर्गत रेत के प्रमुख घाटों में शामिल ग्राम लखना कोलियारी में अवैध रेत उत्तखनन और रेत चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है, अब तो अवैध रेत परिवहन करने वाले लोग रास्ता रोकने वाले ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास करने से भी नहीं हिचक रहे है। हुआ यूँ कि ग्राम कोलियारी में गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात रेत ले जा रहे एक हाइवा के चालक ने रोकने का प्रयास कर रहे ग्रामवासियों को कुचलने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया।

एक आदेश की वजह से महज 28 दिनों में ही कुर्सी गंवा बैठे बिलासपुर कमिश्नर?

बिलासपुर। बिलासपुर कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का को महज 28 दिनों में हटाकर जनक प्रसाद पाठक की पोस्टिंग करने की खबर पर बातचीत शुरू हो हुई थी कि कुछ घंटों के भीतर सरकार ने अचानक पाठक को कमिश्नर बनाए जाने का आदेश वापस ले लिया और रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे को बिलासपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी. अब दो दिनों बाद इससे जुड़े समीकरण सामने आए हैं.

पहली बात नीलम नामदेव एक्का की, जिन्हें 28 दिन पहले ही राज्य सरकार ने बिलासपुर कमिश्नर बनाया था. सूत्र बताते हैं कि एक्का के एक फैसले ने उनकी वापसी के दरवाजे खोल दिए. बताया जा रहा है कि मिशन अस्पताल की लीज से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया था. मिशन अस्पताल शहर के बीचोबीच स्थित है. अस्पताल की लीज करीब सौ साल पुरानी थी, जो सालों पहले खत्म हो चुकी थी. अरबों की इस जमीन का लीज रिन्यू नहीं हुआ था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेदखली का रास्ता

साफ हुआ. हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिलासपुर कलेक्टर ने जमीन से बेदखली का आदेश जारी कर दिया. इस बीच बिलासपुर कमिश्नर की पोस्टिंग मिलने के बाद नीलम नामदेव एक्का ने कलेक्टर की बेदखली आदेश के मामले की सुनवाई करते हुए उस पर स्टे दे दिया. प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि इस फैसले के बाद ही सरकार नाराज हो गई और अगले दो दिनों के भीतर ही उनका तबादला कर दिया. दूसरी अहम जानकारी जनक प्रसाद पाठक को लेकर सामने आई है, जिन्हें कमिश्नर बनाए जाने के आदेश को चंद घंटों में ही वापस ले लिया गया. प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि जांजगीर चाम्पा में कलेक्टर रहने के दौरान उन पर लगे यौन शोषण के आरोप लगने की वजह से उनका तबादला आदेश वापस लिया गया. पाठक इस वक्त हाईकोर्ट से जमानत पर हैं.

जांजगीर चाम्पा जिला बिलासपुर संभाग के अधीन आता है. हाईकोर्ट उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई कर रहा है. भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं की आपत्ति पर सरकार सचेत हो गई और आनन-फानन में आदेश वापस ले लिया गया.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्रवाई- प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि नीलम नामदेव एक्का द्वारा मिशन अस्पताल को बेदखली पर रोक लगाते हुए स्टे दिए जाने के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में लाई गई थी. मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और इस पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश अफसरों को दिए. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप चंद घंटों के भीतर आदेश को अमल में लाया गया. इसी तरह जनक प्रसाद पाठक के मामले पर भी उच्च स्तरीय चर्चा के बाद आदेश वापस लिया गया.

मुठभेड़ में ढेर हुई 18 लाख की तीन ईनामी महिला नक्सली

नारायणपुर। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी 'माड़ बचाओ अभियान' के तहत् उत्तर बस्तर डिवीजन क्षेत्रान्तर्गत नारायणपुर-कांकेर सीमावर्ती हचेकोटी, छिंदपुर, बिनागुण्डा, पांगुड़ के जंगल में लगातार 72 घंटों तक अभियान चलाया था। इसमें वर्दीधारी महिला ईनामी नक्सली मारी गई थी। पुलिस ने 18 लाख की तीन ईनामी महिला नक्सलियों की शिनाख्ती की है। मुठभेड़ में मारी 5-5 लाख के 2 ईनामी और 8 लाख की वर्दीधारी महिला माओवादियों की शिनाख्ती हुई है। मृत माओवादियों का उत्तर-बस्तर डिवीजन के अन्तर्गत एसीएम के रूप में पहचान हुई है। मौके से 303 राइफल, 315 राइफल, बीजीएल लांचर, भरमार बंदूक सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामान व अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद हुई।

मारी गई नक्सली-

(1) नाम- लक्ष्मी, उत्तर बस्तर डिवीजन, निवासी मल्कानगिरी जिला, ओडिशा, ईनामी- 8 लाख।

(2) नाम- सविता, परतापुर एरिया कमेटी, उत्तर बस्तर डिवीजन, मानपुर-मोहला जिले के निवासी, ईनामी- 5 लाख।

(3) नाम- शांता, परतापुर एरिया कमेटी, उत्तर बस्तर डिवीजन, बीजापुर जिले के निवासी, ईनामी- 5 लाख।

स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा- मेकाहारा में तैनात होंगे बंदूकधारी गार्ड

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि, बंगाल की घटना के मद्देनजर राजधानी के मेडिकल कालेज यानी मेकाहारा में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 12 बन्दूकधारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं अस्पताल परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। गलत गतिविधियों को रोकने के लिए अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं अस्पतालों में तीन महीने के अंदर पेट स्कैन मशीन शुरू की जाएगी। वर्चुअल पोस्टमोर्टम के लिए 7 करोड़ की मशीन खरीदी की जाएगी। अम्बेडकर अस्पताल को उत्कृष्ट अस्पताल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

डीकेएस मेकाहारा की पुरानी स्कैन मशीन भी बदली जाएगी और नई एमआरआई मशीन खरीदी जाएगी। डीकेएस अस्पताल में आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 7 करोड़ की लागत से मशीन और लैब बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि, 3 महीने में जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा।

अब नक्सली घटनाओं में घायल जवानों को रायपुर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यादव (ठेठवार) समाज ने निकाली श्रीराधा कृष्णा की विशाल शोभायात्रा

रायपुर। यादव (ठेठवार) समाज रायपुर राज युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राधा कृष्ण जी की विशाल शोभायात्रा, कलश यात्रा राज मुख्यालय भवन महादेव घाट रायपुर से निकाली गई शोभा यात्रा के प्रारंभ में यादवों के ईष्ट देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की विधि विधान से राज ठेठवार श्रीकांत यदु एवं समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात फूलों की वर्षा के साथ श्री कृष्ण जी की घोड़े वाली रथ आगे बढ़ी, विशाल समाजजन हाथों में पीला ध्वज लेकर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाते हुए एक से बढ़कर एक दोहे कहकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया द्य समाज की महिलाओं ने रथ के आगे कलश लेकर शोभा यात्रा की शान बढ़ा रहे थे, सभी ठेठवार जन पटाखे एवं आतिशबाजी कर थिरकने पर मजबूर हो गए द्य रायपुरा चौक पर समाज के पूर्व महासचिव नरेश यादव द्वारा भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए बच्चों से मटकी फोड़ करवाकर माहौल को भक्तिमय में बना दिया द्य शोभायात्रा के सामाजिक भवन पहुंचने पर वहां मुड़पार से आए कलाकारों

ने एक से एक शौर्य प्रदर्शन किया एवं भवन में भी मटकी फोड़ किया गयाद्य शोभा यात्रा कार्यक्रम में राज ठेठवार श्रीकांत यदु, समाज के अध्यक्ष संतोष यदु, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश यादव, महासचिव मनीराम यादव, कोषाध्यक्ष शोभाराम यदु, युवा प्रकोष्ठ महासचिव महतोष यादव, बंशीलाल यादव, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गंगोत्री यदु, महासचिव केशरी यादव, कोषाध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी यदु, रायपुर महानगर संरक्षक डॉ. रेवाराम यदु, युवा प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष परमानंद यादव, रायपुर ह्रदय राम यदु, आत्माराम यदु , नरेश यादव प्रवीण यादव, राज उपाध्यक्ष नवीन यदु, नेतराम यादव, प्रताप यदु, हीराराम यादव, विजय यदु धर्मेंद्र यदु, डॉ. इतवारी राम यादव, उधो राम यदु, कुलेश्वर यादव रघुनंदन यादव, रामस्वरूप यादव, सचिव युगल यदु ,डॉ. इंद्रदेव यदु, कुंज बिहारी यदु, गजानंद यादव, धनेश यादव, रुपेश यादव शशिकांत यदु, गज्जू यादव, सूर्यकांत यदु , बसंत यदु, नीतीश यदु, उपकोषाध्यक्ष लव यदु, चुम्मन यादव, बालेंद्र यदु, दिलीप यादव, यशवंत यादव, देवचंद यादव, कार्यालय सचिव करण यदु, राहुल यदु, बल्लू यादव, अमृत लाल यादव, महानगर महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अंजनी यदु, महासचिव किरण यदु, कोषाध्यक्ष माया यदु, अन्नपूर्णा यदु सरला यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे द्य मंच संचालन कार्य गजानंद यादव ने की , उक्त जानकारी समाज के उपाध्यक्ष नवीन यदु ने दी।

अब मेकाहारा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक ही माना जाएगा : बृजमोहन

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, मेकाहारा अस्पताल, डेंटल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज एवं डीकेएस चिकित्सालय के स्वशासित समिति की बैठक ली। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, मेकाहारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसको देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। जिसमे डीन और डायरेक्टर को 25 लाख रुपए तथा कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा को 3 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं अब मेकाहारा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक ही माना जायेगा। जो टेस्ट मेकाहारा में नहीं होते उन्हें बिना

किसी अतिरिक्त खर्च के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से कराया जा सकेगा जिससे मरीजों और उनके परिवार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की मेकाहारा चिकित्सालय में गामा कैमरा को तीन महीने में चालू करने और अस्पताल में बाय पास सर्जरी के लिए गेस्ट डॉक्टर्स और गेस्ट लेक्चर को बुलाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए है। अस्पताल में एमआरआई स्कैन मशीन और अन्य उपकरण खरीदी की स्वीकृति प्रदान की। कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा को विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए हॉस्टल और अन्य निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजधानी में रोजगार देने के नाम पर ठगी : महिलाओं ने थाने पहुंचकर की शिकायत

रायपुर. राजधानी में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं ने पुरानी बस्ती थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की. महिलाओं ने नारी शक्ति संगठन की संचालिका शोभा ठाकुर और अंगीता श्रीवास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की.

मामले की जानकारी देते हुए पुरानी बस्ती थाने पहुंची कोमल सेन ने बताया, रोजगार देने के नाम पर धोखाधड़ी हुआ है. नारी शक्ति योजना के तहत काम मिलेगा कहा गया था, लेकिन अब तक काम नहीं मिला. बहुत सारी महिलाएं हैं, जिसके साथ ठगी हुई है. प्रार्थी महिला कोमल सेन ने कहा कि शोभा ठाकुर और अंगिता श्रीवास दोनों हमारे मोहल्ले में आए थे और नारी शक्ति संगठन का घर बैठे रोजगार देने की बात कही थी. महिलाओं को एक दो महीने से रोजगार नहीं दिया गया. उसके बाद कहा गया कि खाता खुलेगा तो रोजगार मिलेगा. बिजनेस अकाउंट खोला गया, ताकि उस खाते में आप जितना काम करोगे वह पैसा उसके खाते में सीधे

नारी शक्ति संगठन की संचालिका पर लगाए गंभीर आरोप

आएगा, लेकिन ना ही पैसा आया ना ही रोजगार मिला.

अभनपुर, राजिम में भी गिरोह ने बिछाया है जाल- मामले को लेकर प्रार्थी महिलाओं के साथ पुरानी बस्ती थाने पहुंचे पार्षद दीपेश जायसवाल ने कहा कि नारी शक्ति संगठन हर वार्ड में लगभग 200 से 300, 400 महिलाओं से रुपए लेकर घर बैठे रोजगार देने की बात कह रहे थे, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला. रोजगार किसी एक-दो लोगों को मिला है. हर वार्ड से 100-200 महिलाओं से पैसा लिया गया है. दो महिलाओं को तीन चार दिन काम देते हैं. मेरे वार्ड से 300 महिलाओं से पैसा लिया गया है. चाहे अमलीडो की बात हो, कुकुरबेड़ा की बात हो, अभनपुर, राजिम चारों तरफ इन्होंने अपना जाल बिछाकर रखा है. एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है.

भाटागांव में करीब 400 महिलाओं से लिए हैं पैसा- पार्षद दीपेश ने बताया भाटागांव में संपर्क किया तो वहां 300 से 400 लोगों से 100-100 रुपए लिया गया है. 16 महिलाओं का कर्नाटका बैंक में अकाउंट खुलवाया गया है. खाता खुलवाने के बाद जो इंचार्ज है शोभा ठाकुर उन्होंने एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल नंबर को सील करके अपने पास रखा है. कुछ महिलाओं ने बैंक में संपर्क किया तो उसके बैंक अकाउंट में बेनामी पैसे का भी लेन देन हुआ है. साइबर पुलिस ने उन खातों को बंद कर दिया है. मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है. आज बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पुरानी बस्ती थाने में आकर शिकायत भी की है, ताकि उनके अकाउंट से गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए, ताकि भविष्य में कोई तकलीफों का सामना न करना पड़े.

जांच के बाद होगी कार्रवाई ः थाना प्रभारी- इस मामले में पुरानी बस्ती थाना प्रभारी योगेश कुमार कश्यप ने कहा, ये महिलाएं भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी से आई थी. इनका कहना है कि नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष शोभा ठाकुर ने उनके क्षेत्र में आकर रोजगार देने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पैसा लिया है. उनके नाम से अकाउंट खुलाकर एटीएम कार्ड, पासबुक को अपने पास रखा है और वह मिस यूस कर रहे है. महिलाओं की शिकायत पर पुलिस मामे की जांच कर रही है. इसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी.

एसडीओपी बालोद और थाना प्रभारी बालोद ने काटा 6400 रू का चालान

बालोद। ऐसे टू-व्हीलर्स को बहुत दूर से ही पहचान रहे पुलिसवाले, ज्यादा स्पीड वाहन चलाने वाले लापरवाह वाहन चालकों का काट रहे 6400 रुपए का चालान। लापरवाह वाहन चालक को पुलिस ढूंढकर चालान काट रही है। नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अब बालोद पुलिस काफी सख्त हो गई है। जिसके चलते टू-व्हीलर्स राइडर के तगड़े चालान कट रहे हैं। इनमें सभी तरह की मोटरसाइकल और स्कूटर्स शामिल हैं। दरअसल, जिन गाड़ियों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो पुलिस इन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचान में आ जाती हैं। कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25 हजार तक कर दिया गया है। साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

बालोद एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि भारत में प्रत्येक सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए स्पीड निर्धारित की गई है जिसके अंदर ही आप अपने वाहन को चला सकते हैं, मगर अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में अथवा सिर्फ रोमांच के लिए, तय स्पीड से ज्यादा पर अपना वाहन चलाते हैं, जो न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि इसके चलते काफी गंभीर हादसे भी हो जाते हैं जिसमें वाहन के साथ साथ लोगों की जान का नुकसान अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप दू व्हीलर चलाते वक्त ओवरस्पीडिंग करते हैं। बालोद थाना प्रभारी रविशंकर पाण्डेय ने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिये 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू किया गया जिसमें कठोर प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल में सभी दो पहिया वाहनों के लिए लागू किए गए है। यातायात नियमों के बारे में जिन्हें तोड़ने पर वाहन चालक को जुर्माने से लेकर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर चलने के लिए प्रत्येक वाहन के लिए एक लेन निर्धारित की जाती है जो उनके सेगमेंट और स्पीड पर निर्भर करती है। मगर अक्सर देखने को मिलता है कि दू व्हीलर सवार सड़कों पर अलग अलग लेन में बड़े खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, जिसमें वाहनों को गलत तरीके से टेकओवर करना, स्टंट करना शामिल हैं। अगर दो पहिया वाहन चालक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, तो पकड़े जाने पर उनको 5000 रुपये

कोयला घोटाला मामलाः ईओडब्ल्यू ने सूर्यकांत के भाई को किया गिरफ्तार

रायपुर. कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने एक और आरोपी रजनीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है. वे जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी का बड़ा भाई है. ईओडब्ल्यू ने आरोपी रजनीकांत तिवारी को कोर्ट में पेश कर 14 दिन यानी 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है. ईओडब्ल्यू ने बताया, अवैध कोल लेवी प्रकरण के आरोपी रजनीकांत तिवारी निवासी महासमुंद लम्बे समय से फरार चल रहा था. उनकी पतासाजी पर उसका आगरा में होना पता चला. उसे नोटिस देकर ब्यूरो मुख्यालय तलब किया गया. ब्यूरो मुख्यालय में उपस्थित होने पर उससे पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. आज रजनीकांत तिवारी को विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने 12 सितंबर तक आरोपी को पुलिस रिमाण्ड पर ब्यूरो को सौंपा है.

समाज और राजनीति में जाति का प्रश्न

केसी त्यागी

समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में जाति और राजनीति का आपसी गठजोड़ कम-से-कम 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से हुआ है। जाति की पहचान सत्ता के विचारों से निर्धारित होती है। यह पहचान ऐसी है कि इसे कभी बदला नहीं जा सकता है, जबकि जातिगत पहचानें 'दी' नहीं जाती हैं, बल्कि सामाजिक-सह-राजनीतिक रणनीतियों के अनुसार निर्मित एवं विकसित होती हैं। जातिगत पहचान ऐसी है कि यह जीवनभर आपका पीछा करती रहती है। यही कारण है कि जाति और राजनीति का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ता गया क्योंकि जाति एक जटिल अस्तित्वगत निर्माण है। कई जाति-विरोधी आंदोलनों और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद जाति भारतीय मानस में रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से के रूप में मौजूद है। वैश्वीकरण के आगमन के बाद भी जाति नये रूपों में सामाजिक और आर्थिक विषमता एवं बहिष्कार तथा हिंसा को बढ़ावा देती है। तथ्य बताते हैं कि किस प्रकार वंचित तबकों की पहचान व आवाज को राजनीति ने संसद में आकार देने का काम किया है तथा इनमें नये अर्थ भर दिये गये हैं, जो जातीयकरण की प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। यह सब चुनावी राजनीति तथा सकारात्मक भेदभाव के राजकीय कार्यक्रमों जैसी सार्वजनिक नीतियों के कारण हुआ है, जबकि संविधान विरोधी समुदायों को लगता है कि डॉ आंबेडकर ने तो संविधान में आरक्षण की नीति का प्रावधान केवल 10 वर्ष के लिए किया था, लेकिन जातिगत राजनीति के कारण इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, पर इन समुदायों को यह ध्यान रखना होगा कि समाज में आज भी सामाजिक-आर्थिक विषमता मौजूद है। संविधान विरोधी समुदाय यह भी तर्क देते रहते हैं कि भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। शायद ये समुदाय समझने में विफल प्रतीत होते हैं कि संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, तभी इन वर्गों के इतने सांसद और विधायक चुनकर आते हैं। यदि राजनीतिक आरक्षण नहीं होता, तो विधायिका में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या दिखती है, शायद वह संख्या नहीं होती। उत्तर भारत के अधिकतर बुद्धिजीवी, जो जातिगत ढांचे में फिट होते हैं, वे बिहार व उत्तर प्रदेश को जातिगत राजनीतिक वर्चस्व, दमनकारी जाति और सामाजिक संरचनाओं की कहानियों में डूबा हुआ राज्य मानते हैं, जबकि उन्हें याद रखना चाहिए कि इन राज्यों में 1990 के पहले राजनीति में एक खास वर्ग का वर्चस्व था। आंकड़े बताते हैं कि 1990 से पहले बिहार में 19 मुख्यमंत्रियों में से छह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से थे तथा वे सभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये। उत्तर प्रदेश में 1990 के पहले 14 मुख्यमंत्री बने, जिनमें केवल दो मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से थे। ये आंकड़े केवल मुख्यमंत्री तक भर तक सीमित नहीं हैं। यह वर्चस्व सांसद और विधायक तक में देखने को मिल जायेगा, जहां हमेशा वर्चस्वशाली जातियां ही चुनकर आती थीं, लेकिन खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े 1990 के बाद बदलने शुरू हो गये थे। इस जातिगत राजनीतिक तस्वीर को सबसे पहले बदलने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने वंचित तबकों में राजनीतिक चेतना जागृत की थी। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उनकी सरकार गिरा दी गयी। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत राजनीतिक तस्वीर को बदलने का श्रेय वीपी सिंह को जाता है, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तस्वीर को उलट कर रख दिया। वीपी सिंह का भी वही हश्र हुआ, जो कर्पूरी ठाकुर का हुआ था। प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी का मानना है कि भारत में जाति के राजनीतिकरण ने दलीय राजनीति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्होंने साबित किया है कि जाति का राजनीतिकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। जाति को राजनीति की उतनी ही जरूरत है, जितनी राजनीति को जाति की।

मोदी 3.0 : आत्मविश्वास और शक्ति का संतुलन

अमिय भूषण

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। इस बयान में उन्होंने कहा है की हमने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के निहितार्थ को समझाने के लिए मोदी सरकार के हालिया निर्णय ही पर्याप्त है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मौजूदा स्वरूप पर एक निर्णय आया है। इसमें आरक्षण लाभार्थियों में से सुसम्पन्न परिवारों को बाहर किए जाने की सिफारिश की गई है। दरअसल, कुछेक परिवार ही पीढ़ियों से इसका लाभ लेते आए हैं।

इधर एक बड़ा तबका अब भी विकास से कोसों दूर है। ऐसे में इन अभावग्रस्त परिवारों के उन्नयन हेतु ये आवश्यक है कि इस वर्ग से आने वाले सुसम्पन्न परिवार सुविधाओं का परित्याग करे। इनके द्वारा छोड़ी गई सुविधाओं के लाभार्थी केवल इनकी ही जाति एवं सामाजिक वर्ग के हित में होना है। ऐसा नहीं है कि माननीय न्यायालय ने बिना प्रमाणों एवं विचार के ही अपना मंतव्य रखा है।इसके अपने कारण है दरसल हर शासकीय जनगणना एवं विभिन्न सर्वेक्षणों के उपरांत इस विषमता के साक्ष्य प्रमाण मिलते रहे है। इस नाते कई दलित बुद्धिजीवी एवं नेताओं ने भी आगे आकर बदलाव की बात की है।

इधर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बदलाव का स्वागत किया है। वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस बदलाव को जरूरी बताया है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय पासवान उन गिने-चुने दलित बुद्धिजीवी एवं राजनेता के तौर पर है जो इस बदलाव के हमेशा से हिमायती रहे है। यही नही उन्होंने अपने बच्चों को भी आरक्षण का लाभार्थी बनने नही दिया है। इस बीच इससे मिलते जुलते एक और मामले पर भी मोदी सरकार अपने निर्णय से पलटी मार चुकी है।

अभी हाल ही में भारत सरकार के कुछेक प्रशासकीय पदों पर सीधे नियुक्ति का मामला था, जिनके अंतर्गत विभाग विशेष मे कार्य विशेषज्ञताओं से परिपूर्ण अनुभवी एवं बेहद पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्ति होनी थी।सरकार

के चौबीस मंत्रालयों मे ऐसे करीब पैंतालीस अधिकारियों की नियुक्ति अगले पांच वर्ष के लिए होनी है। ऐसी नियुक्तियों का दुनियाभर में चलन है अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक मे यह प्रभावी है।किंतु इस पर भी राहुल गांधी द्वारा सवाल खड़ा किया गया है।

यहां बजाय इनके उपयोगिता एवं योग्यता पर प्रश्न की जगह नियुक्ति मे आरक्षण न होने को तूल दिया गया है।जबकि एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान ही नही है। वहीं अतीत के कांग्रेस सरकार में ऐसी नियुक्तियों के कई उदाहरण है।जिसके अंतर्गत मनमोहन सिंह,मॉन्टेक सिंह अहुवालिया,रघुराज रामन सैम पित्रोदा एवं सोनिया गांधी लाभान्वित हुई है।किंतु विपक्ष द्वारा बनाये गए मुद्दे को लेकर सरकार यहां भी अपने निर्णय से पीछे हटी है।जिसकी परिणिति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस विज्ञापन के जारी होने के तीसरे दिन इसका निरस्त होना है।वैसे इन मुद्दों का सबसे असमंजसपूर्ण पहलू सरकार मे बैठे लोगो का परस्पर विरोधी वक्तव्यों का आना है।

बात प्रशासकीय सेवा चयन मुद्दे की करे तो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के वक्तव्य बेहद सधे थे।आरक्षित वर्ग आने वाले इस पूर्व नौकरशाह ने इसके विषय मे बेहतरीन दलीलें दी थी। किंतु इसी मुद्दे पर मंत्री चिराग पासवान ने विरोध पूर्ण वक्तव्य देने करने का काम किया।वही सहयोगी दल जदयू ने भी असहमति प्रकट की है।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। वैसे केवल ऐसे दो मामले ही नहीं हैं। इसी महीने केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु एक संशोधन विधेयक लाया था, जिसे विपक्ष के विरोधी तेवर को देखते हुए अकारण संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया, जिसके प्रतिनिधि सत्ता एवं विपक्ष दोनों के सदस्यगण होते हैं। ऐसे में अब इस बात की पूरी आशंका है कि यह प्रारूप अधर में लटकेगा। अगर यह सदन पटल पर आया तो भी अपने मूल सुधारात्मक स्वरूप में कतई नहीं होगा। दरसल लगातार ऐसे संशयात्मा निर्णय सरकार की मनसा,प्रगतिशील सोच एवं बदलाव संबंधित प्रयासों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वहीं यह निश्चित ही विपक्षी दबाव और सत्ता पक्ष के आपसी समन्वय के अभाव का सूचक है। अन्यथा चिराग पासवान तथा नीतीश कुमार की पार्टी सार्वजनिक रूप से भला क्यों विभिन्न मुद्दों पर असहमति प्रकट करती? वहीं वक्फ विधेयक पर तेलगुदेशम द्वारा न्यायिक संवैधानिक पहलुओं के विचार की जगह मजहबी मौलानाओं से संवाद का सुझाव भी निश्चित ही इसी प्रकार का है। ऐसे ही सोच और समझ का परिणाम अब समान नागरिक संहिता की जगह पंथ निरपेक्ष नागरिक कानून की बात है।

प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से इसके लाए जाने की बात की है। जबकि यह नागरिकों के बीच बिना किसी भेदभाव के एक समान अधिकार व्यवहार एवं दंडविधान की वकालत करता है। यह संविधान की मूल भावनाओं की न्याय सम्मत अभिव्यक्ति है। किंतु जब देश के प्रधानमंत्री ही इसे लेकर ऐसे संशय तथा परिवर्तनों वाले सोच से भरे हों, ऐसे में इसका भी हश्र निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

दरसल अतीत के कई ऐसे मसलें हैं जिस पर प्रभावी पहल के बावजूद भाजपा सरकार असफल सिद्ध हुई है। यहां तक कि कई मामलों में तो न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी भाजपा शासन इन निर्णयों पर अडिग नहीं रही। पिछले एक वर्ष से अशांत मणिपुर समस्या का मूल कारण आरक्षण से संबंधित रहा है। यहां के मूल निवासी मैतेई बहुसंख्यक होने के बावजूद आरक्षण दायरे से बाहर होने के नाते कई प्रकार की समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। ये समुदाय अपने ही प्रांत में कहीं भी भूमि क्रय कर बस नहीं सकता है। वही यहां लागू दोहरे आरक्षण विधानों के नाते भूमिपुत्र मैतेई सरकारी नौकरियों मे भी पर्याप्त हिस्सेदारी से वंचित है।

ऐसे में इनके पक्ष में आए न्यायिक निर्णय के बावजूद भाजपा शासन इन्हें आरक्षण दायरे में शामिल करने मे अक्षम सिद्ध हुई है।विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र एवं विपक्षी राजनैतिक दबाब के नाते ऐसे कई घटनाक्रम विगत् वर्षों में हुए है। सन् 2021 मे तेरह महीनों तक चला अराजक किसान आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था। आंदोलन की आड़ में अलगाववादी शक्तियां अराजकता को बढ़ावा दे रही थीं। वहीं यह देश की छवि को खराब करने तथा सरकार को अस्थिर करने का भी उपक्रम था। बात अगर सुधारों की हो तो पूर्ववर्ती सरकारों के समय आए कृषि सुधार प्रस्तावों को तीन कृषि कानूनों के द्वारा इस सरकार में लाया गया था।

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ.स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट जो की कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार के दौरान आई थी वो पूरी की पूरी लागू होनी थी। किंतु मोदी सरकार अपने इस निर्णय पर भी कायम नही रह पाई। वैसे ये मोदी शासन के पूर्ववर्ती कार्यकाल की इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलित उत्पीड़न अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक लगाने का निर्णय दिया है, जिसके उपरांत विरोध प्रदर्शनों को देखकर भाजपा शासन ने इसे संसदीय प्रस्ताव से पलट दिया था। विदित हो कि ऐसा ही एक न्यायिक निर्णय शाहबानों प्रकरण भी हुआ था।

जबकि इन सभी निर्णयों का सीधा संबंध देश के तीव्र गति विकास एवं शांतिपूर्ण सामाजिक ताने-बाने से रहा है। इस बीच सबसे दुखदाई बात है सरकार,भाजपा पार्टी और इससे जुड़े आरएसएस समूह के संगठनों की ऐसे सभी मुद्दों पर निष्प्रभावी पहल और इनका निष्क्रिय एवं आत्ममुग्ध होना। ऐसे में दो ही विकल्प बचते है। देशहित में सरकार ऐसे हर मुद्दे पर जनमानस में एक व्यापक समर्थन तैयार करे। वहीं प्रत्येक मसले पर पूरी तैयारी के साथ आए तथा बिना दबाव के इसे लागू करें और अपने निर्णयों पर बनी रहे।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-8)

गतांक से आगे...

यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे पूर्वजों में सब से बड़ा यह गुण था कि वे राजा-रंक के कौन कहे अपने पूज्य माता- पिता और गुरु के तथा स्वयं अपने भी अणु मात्र दोष को डंके की चोट घोषित कर दिया करते थे। यह कार्य कोई दुर्बलहृदय मनुष्य नहीं कर सकता, इसके लिये महान् आत्मा-सम्पन्न होने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों श्री गाँधी ने स्वलिखित आत्मकथा प्रकाशित की थी। उक्त कथा में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो कि मानव सुलभ कमजोरियों से भरपूर होने के कारण अत्यन्त लजास्पद हैं, परन्तु किसी भी मनुष्य को उक्त घटना के पढ़ने से गाँधी जी के व्यक्तित्व पर घृणा हुई हो सो बात नहीं, बल्कि जो भी पढ़ता है उनकी स्पष्टवादिता पर मुग्ध हुये बिना नहीं रहता। कल्पना कीजिये कि सौ वर्ष के बाद कोई मनुष्य उक्त लज्जास्पद अंशों को उनके विरोधियों द्वारा प्रक्षिप्त कहने लगे तो यह कहाँ तक न्याय होगा? इसी प्रकार आजकल अंग्रेजों में यह रिवाज है कि वे स्त्री-पुरुष इकट् होकर नृत्य करते हैं और वहाँ के पाहुने विदा होते समय सम्बन्धियों की महिलाओं का मुख चुम्बन करते हैं, तथा ऐसा करना वे सर्वथा सभ्यता के अनुकूल समझते हैं, परन्तु भारतीय महिलाओं के साथ पत्यन्तर पुरुष का ऐसी चेष्टा करना सरफुटब्बल काण्ड का कारण समझा जाता है। कल्पना कीजिये कि भारतीयों के संसर्ग से यह योरूपियन रिवाज क्रमशः विलुप्त हो जाए और अंग्रेजों की आने वाली सन्तति भी हमारी तरह इसे लज्जास्पद समझ कर आजकल के लिखे गये ग्रन्थों में सौ वर्ष के बाद इस तथ्य को दूतरों की मिलावट कहने लगे तो यह कहाँ तक सत्य होगा? इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पुराण और इतिहास में जो ऐतिहासिक वृत्तान्त जैसे लिखे हैं, उनके ज्यों के त्यों बने रहने पर भी फिर चाहे वे धर्मविरुद्ध हो या वर्तमान रिवाज के प्रतिकूल हों। **क्रमशः ...**

लक्षद्वीप के द्वीप : सुंदरता से ज्यादा, एक अद्भूत पारिस्थितिकीय रहस्य

सिद्धी जयशंकर

लक्षद्वीप के द्वीप इस साल काफी चर्चा में रहे हैं। उनके सफेद रेतीले तट और नीले लैगून ने इन्हें बहुत से लोगों की यात्रा की सूची में शामिल कर दिया है। लेकिन, हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये द्वीप वास्तव में कितने अद्भुत हैं।

लक्षद्वीप के द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विपरीत, एटोल्स (प्रवाल द्वीप) की श्रृंखला में आते हैं। इसका मतलब है कि इनका आधार लगभग पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जो प्रवाल (यानी कि कोरल्स) और अन्य समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। यही रीफ इन द्वीपों का अस्तित्व सुनिश्चित करता है और उन्हें लहरों और तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रवाल रीफ समुद्र के वर्षावनों की तरह होते हैं, जो कई प्रकार के

जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को घर प्रदान करते हैं। इसीलिए, ये जीव स्थानीय मत्स्यपालन और द्वीपवासियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

रोजाना इन जीवों के बीच कई प्रक्रियाएं और इंटरैक्शन होते हैं। जैसे कि सबसे छोटे प्लांकटन से लेकर बड़े जीवों तक, सबका भोजन श्रृंखला में योगदान होता है, जो स्थानीय मत्स्यपालन को सहारा देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि ये जीव द्वीपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। प्रवाल समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, जो अपने नरम शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की संरचनाएं बनाते हैं। ये संरचनाएँ समय के साथ और अधिक प्रवालों और अन्य जीवों द्वारा बनाई जाती हैं, और इस प्रकार प्रवाल रीफ का निर्माण होता है।

साथ ही, कुछ जीव रीफ का अपरदन भी करते हैं। पैरेटफिश—जिनके बड़े, खरगोश की तरह सामने के दांत होते हैं—प्रवाल के टुकड़े काटकर उसमें बसने वाले शैवाल (या ऐल्गे) को खाते हैं। इनमें से कुछ पैरेटफिश प्रवालों पर उग रहे शैवाल को खुरचते हैं और इस प्रक्रिया में नीचे मौजूद मृत प्रवाल को भी खुरच लेते हैं। समुद्री अर्चिन, जो समुद्र में कांटेदार गोल जीव होते हैं, भी यही काम करते हैं। लक्षद्वीप में एक विशेष प्रकार का समुद्री अर्चिन भी अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह रीफ में खुदाई कर उसमे खोखले छेद बना देता है। ये सभी जीव प्रवाल को छोटे-छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जो बाद में धाराओं द्वारा अन्य द्वीपों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ बालू का निर्माण करते हैं। इसके अलावा, हवा और लहरों जैसी अजैविक ताकतें भी मृत प्रवाल को घिसकर बालू का निर्माण करती हैं। एक्रोपोरा - एक तेजी से बढ़ने वाला लेकिन नाजुक प्रवाल, जिसमें मछलियां छुपी हुई हैं। रीफ में वृद्धि प्रक्रिया, अपरदन के मुकाबले मे, तेजी से होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और रीफ को पनपने के लिए एक विशेष गहराई पर रहने की आवश्यकता है, जो केवल तभी हो सकता है जब रीफ समुद्र के स्तर के साथ-साथ बढ़ता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, विकास के दबाव, और अन्य कारणों से प्रवाल मर रहे हैं।

पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संवारने में हमारी विदेश नीति विफल

मोहन लाल

इसे भारत दुर्भाग्य ही समझेगा कि पड़ोसी मुल्कों से इसके संबंध कभी मधुर नहीं रहे। पड़ोसी देशों से अपने संबंध बनाने में हमारी विदेश नीति हमेशा लुटकती रही। पड़ोसी देश हमारे शत्रु ही बने रहे। यह तो सत्य है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ पनपते नहीं, परन्तु भारत तो सदैव 'पीसफुल को-एग्जिस्टैंस' का हिमायती रहा है। इसका तो मूलमंत्र ही 'जियो और जीने दो' रहा है। सब सुखी रहें, सबका मंगल हो तो भी भारत टूटता ही रहा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कभी श्रीलंका दक्षिण भारत के चोल और पांड्या राजाओं के अधीन रहा। 1310 में श्रीलंका भारत से अलग हो गया। आज श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है। वर्तमान नेपाल देश कभी भारत का हिस्सा था। 1816 में एक नया देश बन गया। भूटान 1907 में भारत से कट कर एक अलग देश बन गया। अफगानिस्तान और ईरान भारत में थे। परन्तु 1919 में अफगानिस्तान स्वतंत्र देश बन गया। ईरान हमें छोड़ एक कट्टर इस्लामी देश बन गया। कभी ईरान और अफगानिस्तान ड्क्षहदू राष्ट्र थे। 1947 में भारत का एक बार पुनः विभाजन हुआ और इसी भारत का एक अंग पाकिस्तान और बंगलादेश बन गया। मित्रो, सज्जनो, भारत प्रेमियो, विदेश नीति की मूलभूत बातों को समझ लो। पड़ोसी देशों के मध्य उस देश की भौगोलिक स्थिति, उस देश की आर्थिक दशा, उस देश का सैन्य बल, उस देश की आंतरिक स्थिरता और वहां की जनता में आपसी सद्भाव सब कुछ भारत के अनुकूल फिर भी हमीं से निकला देश हमारा शत्रु? क्यों? क्योंकि हमने विदेश नीति पर गंभीरता से चिंतन ही नहीं किया।

यह भी सत्य है कि हम पड़ोसी को कहीं अन्य स्थान पर नहीं भेज सकते। दूर नहीं भेज सकते। परन्तु उसे अपना बनाने की नीति तो बना सकते हैं? कूटनीति को अपना सकते हैं? चाणक्य तो बन सकते हैं? न हमारी कूटनीति पड़ोसी देशों के साथ सफल हुई, न हम चाणक्य बन सके। अतः देश हमारी विदेश नीति के कारण सिकुड़ता चला गया। परन्तु इस पर भी हमारे पड़ोसी देश हमारे न बन सके। विदेश नीति

पर बोलते हुए देश के पहले और प्रगतिशील प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू ने कहा था कि शांति केवल हमारी आशा ही नहीं अपितु हमारी आवश्यकता है। शांति हमारा स्वभाव है। शांति में ही हमारी प्रगति है। शांति हमारी प्राचीन धरोहर है। हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। सबका मंगल हो यह हमारी प्रार्थना है इसीलिए उन्होंने 'पंचशील' सिद्धांत को अपनाया। हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं है। हम निष्पक्ष और तटस्थ रहेंगे। किसी भी ब्लाक का हिस्सा नहीं बनेंगे।

हमारी विदेश नीति सिर्फ भारत का हित साधना है। 'जियो और जीने दो' हमारी विदेश नीति का नारा है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। विस्तारवाद कभी हमारी विदेश नीति का हिस्सा नहीं रहा। हमारी विदेश नीति 'पीसफुल को-एग्जिस्टैंस' शांतमय पारस्परिक सह-अस्तित्व से आगे बढ़ रही है। बस इसी को हमारी कमजोरी समझ विदेशी आक्रमणकारी हमें लूटते रहे, हम पर राज करते रहे। हम पंचशील के सिद्धांत पर चलते रहे और चीन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहा। 1962 में इसी पंचशील ने चीन को हम पर आक्रमण करने पर आमादा किया।

पंचशील का सिद्धांत चीन ही लेकर आया था। चीन ने ही आश्वासन दिया था कि हम प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता और सार्वभौमिकता का सम्मान करेंगे, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी देश के आंतरिक मसलों में दखल नहीं देंगे, आपसी हितों को बराबर सम्मान देंगे, पारस्परिक सौहार्द से प्रत्येक देश को आगे बढ़ने का मौका देंगे। चीन ने सब सिद्धांतों, जो वह स्वयं लेकर आया, की धज्जियां उड़ा कर रख दीं। भारत की प्रभुसत्ता और सार्वभौमिकता को पैरों तले रौंद दिया 1962 में। आज चीन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की पीठ पर खड़ा होकर हमें ललकार रहा है। कहां खड़ी है हमारी विदेश नीति? चीन और पाकिस्तान को लेकर हमारी विदेश नीति फेल है। मानता हूं नरेंद्र मोदी बड़े कद्दावर नेता हैं। विदेशों में मोदी की तूती बोलती है। रूस और अमरीका के राष्ट्रपति उन्हें गले लगाते हैं। सारा यूरोप मोदी के कसीदे पढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें देश का सर्वोत्तम अवार्ड प्रदान किया है। बंगलादेश का हिंदू मर रहा है। पाकिस्तान अपने आतंकी जम्मू-कश्मीर में भेज रहा हूं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। म्यांमार में सैनिक तानाशाही है। वहां की एक महिला नेता सू की लोकतंत्र की बहाली के लिए जेल में सड़ रही है। म्यांमार से भारत में पलायन जारी है। बंगलादेश का हिंदू रिफ्यूजी बनकर हमारी सरहदों पर घुसने के प्रयास में है। ऐसे में नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस में युद्धबंदी करवाने में व्यस्त हैं। फिलिस्तीन और इसराईल में घोर युद्ध छिड़ा है।

ईरान ने इसराईल को मिसाइलों से भून देने की चेतावनी दे डाली है। सारे इस्लामिक मुल्क फिलिस्तीन की सैन्य सहायता के लिए उमड़ पड़े हैं। अमरीका ने इसराईल और यूक्रेन को पूर्ण सैन्य सहायता दे रखी है। इन हालात में हमारी विदेश नीति मूक बनकर खड़ी है। विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी को भारत का हित सोचना चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों ने हमें घेर रखा है। हमारी विदेश नीति को जंग क्यों लग गया है? ठीक है कि 1991 तक सोवियत यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मसले पर भारत का साथ देता आया था परन्तु गर्वाचौव के राष्ट्रपति पद त्यागते ही रूस का वह रूप शायद हमारी मदद करने वाला न रहा।

फिलहाल तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी के दोस्त दिखाई दे रहे हैं परन्तु कल का किस को पता? अतः भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार डोभाल विदेश नीति को भारत के हित में जोडने का प्रयास करें। हमारी विदेश नीति का मूल आधार ही 'राष्ट्रहित' होना चाहिए जो आज भारत की विदेश नीति में दिखाई नहीं देता। पड़ोसी देशों ने भारत से अपनी शत्रुता के बिगुल बजा दिए हैं। पाकिस्तान कभी भारत का अंग था। भाई होने के नाते उसने अपने घर का बंटवारा कर लिया। बंटवारा कर लिया सो कर लिया। वह अपने घर में राजी, हमें अपने देश पर गर्व। परन्तु पाकिस्तान तो भारत का पक्का दुश्मन बन गया। उसने अफगानिस्तान, चीन और अमरीका को अपना बना लिया। फिर एक के बाद एक भारत पर आक्रमण करता चला गया।

सितम्बर 1947 को ही पाकिस्तान ने कश्मीर में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया और जम्मू-कश्मीर के बहुभाग पर कब्जा कर लिया। तब से आज तक पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाता चला आ रहा है। नित नए-नए आतंकवादी आई.एस.आई. से ट्रेनिंग लेकर जम्मू-कश्मीर में मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आज बंगलादेश की प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए हुए है। बंगलादेश में कट्टर-इस्लामी हिंदुओं के घरों, दुकानों, उनकी धन सम्पत्ति को सरेआम लूटकर ले जा रहे हैं। बंगलादेश का हिंदू भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है और वहां की सरकार कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बनी हुई है। अतः मेरा निवेदन मोदी सरकार से है कि भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार किया जाए।

भारत का हिंदू विशाल दिल वाला है, उदार है। परन्तु हमारी विदेश नीति हिंदू को कायर न बनाए। भारत के गौरव को पुनः जागृत करो। समय रहते अपने पड़ोसी देशों से या तो वार्तालाप करो या उन्हें भारत की ताकत का इजहार करवाओ। कायरों की तरह सिर्फ फोकी धमकियां मत दो। एक बार आर-पार होने दो।

आज का इतिहास

1952 ग्रेज़लैंडरिंग रेकेट्रैक, वेगबर्ग, जर्मनी में बंद किया गया।
1955 टेक्सास के लुफकिन में पहला माइक्रोवेव आधारित टीवी स्टेशन की स्थापना की गई।
1957 ब्रिटिशों ने मलाया के अपने उपनिवेश को सत्ता सौंप दी है, फिर भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में इसका अस्तित्व बना रहेगा।
1964 कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बना।
1965 एयरो स्पैक्लाइन सुपर गप्पी, एक बड़े, व्यापक शरीर वाले कार्गोएयरक्राफ्ट, जो बाहरी कार्गो घटकों को फेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ने अपना पहला निर्माण किया।
1982 66 पोलिश शहरों में सरकार-विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए, जो डांस्क समझौते की दूसरी वर्षगांठ को मनाने के लिए, सॉलिडैरिटी ट्रेड यूनियन की स्थापना के लिए कहा गया।
1987 माइकल जैक्सन ने अपना हिट एल्बम बुरा जारी किया।
1992 फिलीपींस की खान में डायनामाइट विस्फोट; 500 की मौत।
1997 ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी डोडी अल-फायद पेरिस में एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार एक फुटपाथ से जा टकराई थी। उस समय डायना की उम्र सिर्फ 36 साल थी।
1998 उत्तर कोरिया ने अपने पहले उपग्रह, क्वांगम्योंगसॉन्ग -1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का दावा किया, हालांकि लॉन्च से कक्षा में कोई वस्तु नहीं निकाली गई।
1998 उत्तरी कोरिया ने जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा।
1999 ब्यूनस आयर्स में एक बोइंग 737 फ्लाइट 3142, जो कि लिनेस एरीस प्रिवैडस अर्जेंटिनास से जुड़ी थी, उड़ान भरने के तुरंत बाद लगभग 69 लोगों की मौत हो गई।
2005 बगदाद में मची भगदड़ में लगभग 1,200 लोग मारे गए। कारण यह था कि जब हजारों शिया मुसलमान एक धर्मस्थल की ओर मार्च करने लगे थे।
2005 ईराक की राजधानी बगदाद में अल-आईम्माह पुल पर मची भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
2007 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अस्पष्टीकृत बीमारी के उन्मूलन की घोषणा की, जिसमें उच्च मृत्यु दर है, कसाई के क्षेत्र में रक्तस्रावी बुखार का एक रूप प्रकोप का कारण माना जाता है।
2009 इंग्लैंड और वेल्स में समलैंगिकों को समान जन्म का अधिकार दिया जाता है।
2010 इराक़ में 2003 से जारी अमरीकी सैन्य अतिक्रमण आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।
2010 बेलौर जीनस डायनासोर के जीवाश्म रोमानिया में खोजे गए हैं।

जम्मू कश्मीर में किसका खेल बिगड़ेंगे ये 36 दल!

आशीष तिवारी

जम्मू कश्मीर में सियासत चरम पर पहुंच रही है। आखिरकार 10 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़े राजनीतिक दल तो सक्रियता के साथ सियासी मैदान में डटे ही हैं। लेकिन छोटे-छोटे राजनीतिक दलों से लेकर बड़े-बड़े नेताओं के नए बने दल भी अपनी सियासी चौसर सजाने में लगे हुए हैं। हालात यह हो गए हैं कि कभी जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी चुनावी पार्टियां ही सियासी मैदान में दो-दो हाथ करने को उतरती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के आंकड़ों में ही जम्मू कश्मीर से तकरीबन तीन दर्जन छोटे-बड़े राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। सियासी जानकारों की मानें तो तो यह सभी छोटे-बड़े दल इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपने प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। इसमें कुछ नए राजनीतिक दल तो ऐसे भी हैं जिनके नेताओं का जम्मू कश्मीर के सियासत में अपना एक वजूद हुआ करता था। यही वजह है कि सियासी जानकार आने वाले चुनाव में इन छोटे दलों की हैसियत को कमतर नहीं आंक रहे हैं।

अगले कुछ दिनों में होने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने सियासी मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी समेत अवामी लीग, अवामी नेशनल कांफ्रेंस समेत बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सियासी मैदान में ताल ठोकने को उतर चुके हैं। 10 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मुख्य रूप से यही दल सियासी मैदान में सबसे प्रभावी रूप से सक्रिय थे। लेकिन बीते 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बदली सियासत के चलते कई छोटे-छोटे राजनीतिक दलों का गठन हो गया। इसमें कांग्रेस और पीडीपी से अलग हुए दो बड़े नेताओं के राजनीतिक दल भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बना ली। तो वही पीडीपी से बागी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी सियासी राह अलग करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाम से राजनीतिक दल का गठन कर सियासत में ताल ठोक दी। देश की प्रमुख पार्टियों के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के यह दो नेता भी अपनी नई पार्टी के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना रहे हैं।

केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीते चार वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा दल जम्मू कश्मीर की सियासत में सामने आए हैं। इन सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है ताकि विधानसभा के चुनावी मैदान में वह अपने प्रत्याशी उतार सके। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जिन दलों ने बीते कुछ वर्षों में ही अपने दल को राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर्ड कराया है, उसमें जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट, नेशनल आवामी यूनाइटेड

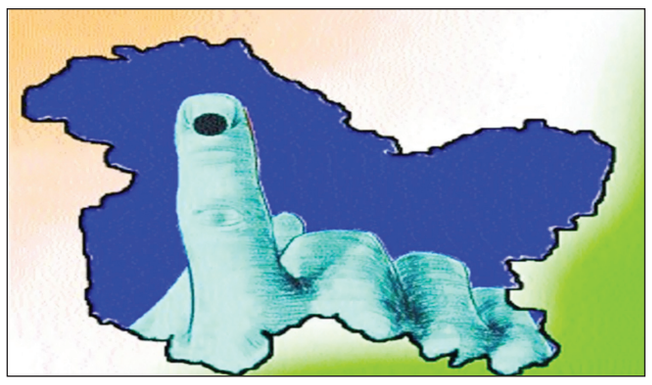

पार्टी, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, वॉइस ऑफ़ लेबर पार्टी, तहरीक ए जम्मू कश्मीर, अमन और शांति पार्टी, एकजुट जम्मू पार्टी, इंसाफ ए हक पार्टी समेत तकरीबन डेढ़ दर्जन सियासी दलों ने चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ नए दलों के रजिस्ट्रेशन के साथ इनकी संख्या तकरीबन तीन दर्जन के करीब पहुंच चुकी है। अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी भी सियासी मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह जरूर हो जाता है कि जो राजनीतिक दल या बड़े नेता पिछले विधानसभा के चुनाव में दूसरे दलों के साथ सियासी पारी को अंजाम दे रहे थे वह इस बार किसका खेल बिगाड़ने की हैसियत में है। जम्मू कश्मीर की सियासत को करीब से जानने वाले पनून कश्मीर के ओपी रैना कहते हैं कि अभी तक कुछ वर्षों में जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने सियासी नजरिए से दलों का गठन किया है, उनमें से सभी सियासी खेल बिगाड़ेंगे इसकी संभावना है ना के बराबर है। क्योंकि बहुत से राजनीतिक दल ऐसे भी बने हैं जो कि पुराने समय में किसी ने किसी रूप में राजनीतिक दलों का समर्थन करते आते थे। क्योंकि उनका उस वक्त भी उतना वजूद नहीं होता था। इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि नई पार्टी बना लेने से वह राजनीतिक दल कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे।

हालांकि रैना का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जब अपनी सियासी पार्टी से प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं उसका असर जरूर देखा जा सकता है। इसी तरह पीडीपी के बागी नेता अल्ताफ बुखारी की पार्टी भी कुछ हद तक एक विशेष क्षेत्र में प्रभाव डाल सकती है। लेकिन यह कहना कि यह सभी दल बड़े स्तर पर व्यापक प्रभाव डालेंगे यह फिलहाल अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। रैना कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत को अब बिल्कुल एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। विधानसभा के चुनाव भी इस नए नजरिए के साथ हो रहे हैं। वह कहते हैं कि अभी विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ब्लॉक फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाकर जम्मू कश्मीर में सियासत की एक नई हवा बहा दी है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी जम्मू कश्मीर में कर रही है।

हालांकि छोटे-छोटे दलों की सियासत में एंट्री को लेकर स्थानीय सियासी जानकार मकबूल अहमद बट मानते हैं कि इस बार पहले की तुलना में बदला हुआ चुनाव देखने को मिलेगा। वह कहते हैं कि छोटे-छोटे दलों का सियासी मैदान में उतारने का सीधा मतलब है कि वह अपनी हिस्सेदारी लोकतंत्र में चाहते हैं। यही वजह है कि कभी जो लोग बड़े दलों के समर्थन में जुटते थे वह अपना राजनीतिक दल बनाकर सियासी मैदान में उतर रहे हैं। बट का मानना है की जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों में शामिल नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और जेकेपीसी जैसे राजनीतिक दलों के लिए इस चुनाव में चुनौती तो होगी। क्योंकि जिन सियासत करने वालों ने नई पार्टियों का गठन किया है उनमें से बहुत से लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की इन्हीं छोटी-छोटी और बड़ी पार्टियों को पहले समर्थन किया करते थे। लेकिन इस चुनाव में बहुत से लोगों ने अपना सियासी दल बनाकर स्थानीय लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की है।

अपनी कथनी-करनी के प्रति जवाबदेह हों नेता

विश्वनाथ सचदेव

टीवी पर अदालत से संबंधित एक कार्यक्रम आया करता है, इस अदालत के 'वकील' से किसी ने पूछा था, 'अभिनेता अच्छे नेता होते हैं या नेता अच्छे अभिनेता', तो 'वकील साहब' को यह कहने में तनिक भी देरी नहीं लगी कि नेता अच्छे अभिनेता होते हैं! और इस उत्तर पर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई थींङ्क अर्थात श्रोता भी यह जानते-मानते थे कि हमारे नेता अच्छे अभिनेता हैं! नेता-अभिनेता वाला यह प्रसंग अचानक तब याद आ गया जब एक नई-नई नेता बनी अभिनेत्री को किसान-आंदोलन के संदर्भ में यह कहते सुना कि हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसी सांस में उसने यह भी कह दिया कि साल भर से

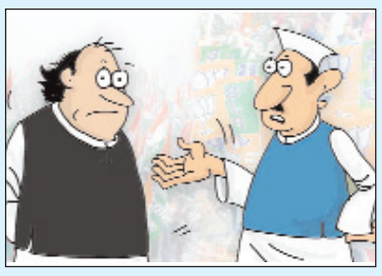

अधिक समय तक चलने वाले उस आंदोलन में 'लाशें लटकी हुई थीं और बलात्कार हो रहे थे।' यह सही है कि उस आंदोलन के दौरान लगभग सात सौ किसानों की मृत्यु हुई थी, पर उसे 'लाशें लटकना' कहना क्या मायने रखता है, यह बात शायद उस अभिनेत्री को समझ नहीं आई थी, और फिर किसान आंदोलन को कथित बलात्कारों से जोड़ने से कितना राजनीतिक नुकसान हो सकता है, यह भी उसकी समझ से परे की बात थी। ऐसे अवसर पर बड़ी आसानी से राजनीतिक नेतृत्व यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि यह कथित नेता का निजी बयान है. सवाल उठता है, इस तरह की निजी राय रखने वाले व्यक्ति को राजनीतिक पार्टियों तरजीह ही क्यों देती हैं? किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होने का सबसे महत्वपूर्ण मतलब यह होता है कि व्यक्ति पार्टी की रीति-नीति में विश्वास रखता है। उसका आचरण इसी विश्वास के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में नीतियों के आधार पर राजनीतिक दलों का बनना और चलना अब कतई आवश्यक नहीं रहा! रीतियों-नीतियों को लेकर दावे जरूर किए जाते हैं, पर व्यवहार में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा न होता तो नेताओं का आए दिन दल बदलना हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं बनता। न किसी व्यक्ति को दल बदलते हुए कोई शर्म आती है और न ही किसी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने में कोई संकोच होता है जिसे वह कल तक भ्रष्ट, अपराधी और न जाने क्या-क्या कहकर दुत्कारा करता था। मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट देते समय जिन दो बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखता है, उनमें पहली व्यक्ति की वैयक्तिक ईमानदारी है और दूसरी उसके दल की रीति-नीति। दुर्भाग्य से, अब हमारी राजनीति में इन दोनों बातों का महत्व नहीं रह गया है- महत्व सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ साधने का है। हमारे नेता यह मानकर चलते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है. आवश्यकता उनकी इस धारणा को गलत सिद्ध करने की है। नेताओं द्वारा कही गई हर बात और किया गया हर काम जनता की अदालत में रखा जाना चाहिए. फैसला करने का अधिकार देश की जनता का है, इसलिए जनता का दायित्व बनता है कि वह नेतृत्व के आचरण पर कड़ी नजर रखे। पांच साल में एक बार वोट देना ही पर्याप्त नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे वोट से नेता बना व्यक्ति अपने वादों और दावों पर खरा उतर रहा है कि नहीं।

दो परमाणु सम्पन्न देशों के बीच बेहतर संबंधों की जरूरत

अशरफ जहांगीर काजी

भारत -पाकिस्तान के रिश्ते इतने लंबे समय तक कभी इतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। एक ध्रुवीकृत लेकिन परस्पर निर्भर दुनिया में, जब प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन पड़ोसी परमाणु हथियार संपन्न देशों, जिनमें से एक की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और दूसरे की पांचवीं सबसे बड़ी आबादी है, के बीच बेहतर संबंधों की जरूरत स्पष्ट होनी चाहिए।पाकिस्तान, दोनों देशों में से छोटा देश होने के नाते, कम से कम न्यूनतम आदान-प्रदान और सहयोग को बहाल करने और अधिक गंभीर मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से कैसे संबोधित किया जाए, इस पर अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष चर्चा को बहाल करने में अपेक्षाकृत अधिक रुचि रखता है।

इसके विपरीत भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी ठोस बातचीत में कमोबेश पूरी तरह से अरुचि दिखाई है। वह पाकिस्तान को एक असफल आतंकवादी देश के रूप में देखता है, जिसके पास बहुत कम विकल्प हैं जिनसे उसे केवल खुद को बचाने की जरूरत है। तदनुसार, वह ऐसे देश के साथ चर्चा में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं देखता। चर्चाएं, भले ही मैत्रीपूर्ण और विनम्र हों, एक-दूसरे के प्रति आधिकारिक, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए आरोप-प्रत्यारोप में बदल जाती हैं।

प्रश्न उठता है कि अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, व्यापारियों, सभी प्रकार के पेशेवरों और विशेषज्ञों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों, छात्रों, पर्यटकों आदि सहित दोनों देशों के लोगों का एक व्यापक स्पैक्ट्रम एक-दूसरे के साथ अधिक से अधिक बातचीत कैसे बढ़ा सकता है जो समय के साथ एक-दूसरे के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? ऐसी प्रक्रिया के अभाव में, किसी भी मुद्दे पर चर्चा, चाहे वह कश्मीर हो, आतंकवाद हो, जल मुद्दे हों, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो, व्यापार और निवेश बढ़ाना हो, विश्वास निर्माण के उपाय हों या पिछली वार्ताओं के एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दे हों, निरर्थक हो जाती है। तो, दोनों देशों के बीच चर्चाएं अधिक फलदायी कैसे हो सकती हैं? 2 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।

पहला, वार्ताकारों को एक ऐसा उद्देश्य सांझा करना चाहिए जिसे वे प्राप्त करने योग्य मानते हों। दूसरा, वार्ताकारों में आत्मनिरीक्षण करने और एक-दूसरे की ड्क्षचताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। यह आसान नहीं है। हाल ही में, जब एक भारतीय परिचित ने पूछा कि भारत-पाकिस्तान संबंध कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान खुद से पूछ सकता है कि वह कुछ भारतीय ड्क्षचताओं को दूर करने के लिए क्या कर सकता है और भारत को भी इसी तरह खुद से पूछना चाहिए कि वह पाकिस्तानी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि भारत को पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह कश्मीर को भूल जाए, आतंकवाद को रोके, स्वीकार करे कि वह भारत के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा हार चुका है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार करे और तदनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को समाप्त कर दे। मैंने सुझाव दिया कि उन्होंने भारत के लक्ष्यों को स्पष्ट किया होगा, लेकिन पाकिस्तान की ड्क्षचताओं को दूर करने की किसी भी इच्छा से प्रेरित नहीं दिखे। इसके बजाय, वह संभवत- एक समान प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे कि भारत आधिपत्य, हस्तक्षेप, हत्या, नरसंहार आदि की नीतियों से दूर रहे। इससे, निश्चित रूप से चर्चा समाप्त हो जाएगी।

तो, क्या हम इस तरह के बंजर आदान-प्रदान से आगे बढ़ सकते हैं? जहां तक कुछ आरोप उचित हो सकते हैं, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए, भले ही एकतरफा हों। क्या हम अपने देशों के बीच कुछ लंबित मुद्दों पर, जिनमें मुख्य ड्क्षचता के मुद्दे भी शामिल हैं, एक ठोस बयान दे सकते हैं, साथ ही सहमत सिफारिशें भी कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी संबंधित सरकारों को विचार के लिए भेज सकते हैं? आपसी सहानुभूति को देखते हुए, न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि अलग-थलग पड़े पड़ोसी देशों के नागरिकों के रूप में भी, जो बहुत कुछ सांझा करते हैं, हम एक सांझा लेकिन अशांत इतिहास की बाधा को दूर करने की दिशा में प्रगति करना शुरू कर सकते हैं जिसने एक-दूसरे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को 'अधिक आकार' दिया है।

इसके बजाय, हम एक-दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बताने और व्यापक बनाने के लिए जो कुछ भी सांझा करते हैं, उसके लिए अधिक जगह दे सकते हैं। ऐसी बातचीत को धीरे-धीरे ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 और आधिकारिक स्तरों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या हम सार्क को पुनर्जीवित करने पर सहमत हो सकते हैं, जो वर्तमान में मरणासन्न है?

क्या हम विश्वास और सुरक्षा निर्माण उपायों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जिन पर सहमति हो चुकी है, उन्हें लागू किया जा चुका है, और रद्द कर दिया गया है या अप्रचलित होने दिया गया है? क्या हम आज की परिस्थितियों में, जोखिमों के बावजूद, संबंधों में सुधार की संभावनाओं की गंभीरता से जांच करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटा सकते हैं? या फिर क्या प्रतिपक्षी ताकतें बहुत मजबूत हैं और उन्हें मात देने की इच्छाशक्ति बहुत कमजोर है?

भारतीयों और पाकिस्तानियों की एक पूरी नई पीढ़ी को एक-दूसरे के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है और वे एक-दूसरे के बारे में ऐसा क्यों सोचते और महसूस करते हैं। उन्हें पता चल सकता है कि वे जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक बातों पर सहमत हैं। अगर ऐसा होता है, तो एक-दूसरे की चिंताओं को संबोधित करना आज की तुलना में बहुत कम मुश्किल हो सकता है। सभी प्रकार के आदान-प्रदान के साथ, आपसी समझ और आपसी लाभ के लिए लॉबी उभर सकती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। ऐसी लॉबी का अपने देशों की राजनीति और सरकारी निर्णय लेने में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव होने की संभावना है।

अब जापान के खिलाफ आक्रामक क्यों हो रहा चीन?

अविनाश द्विवेदी

जापान ने दावा किया है कि चीन के सैन्य विमान ने उसकी वायुसीमा में बड़ी घुसपैठ की है। चीन का सैन्य टोही विमान वाई-9, जापान के एक छोटे से निर्जन द्वीप डान्जो के पास जापानी वायुसीमा में दाखिल हुआ। यह जापान के चार प्रमुख द्वीपों में से एक क्यूशू के पास स्थित है। घुसपैठ की नई घटना पर जापान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है।

जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हायाशी ने कहा, यह जापान की संप्रभुता का गंभीर हनन ही नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जापान की ओर से भविष्य में ऐसी किसी गतिविधि पर हर संभव कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। जापान पिछले कुछ वर्षों से चीन को अपनी सीमाओं के लिए खतरे की तरह देख रहा है।

चीनी सैन्य विमान 26 अगस्त को जिस डान्जो द्वीप के पास जापानी हवाई क्षेत्र में घुसा, वह जापान और चीन के बीच विवादित इलाके का हिस्सा नहीं है। जापानी और चीनी सैन्यपोत पहले पूर्वी चीन सागर के इलाके में एक-दूसरे के आमने-सामने आ चुके हैं। अतीत में ऐसी गहमा-गहमी उन द्वीपों को लेकर हुई है, जिनपर चीन अपना दावा जताता है। इनमें सबसे प्रमुख सेनकाकू द्वीप है। चीन इसे द्याओयू कहता है और इसे अपना इलाका बताता है।

जापान की सेना ने बताया है कि चीन के नागरिक विमान पहले भी जापानी वायुसीमा में दाखिल होते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब चीन के किसी सैन्य विमान ने ऐसा किया है। सेना की ओर से बताया गया कि मार्च 2024 से पहले के एक साल में 660 बार जापान ने घुसपैठ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इनमें से दो-तिहाई कार्रवाइयां चीन के विमान या पानी के जहाज की घुसपैठ के खिलाफ की गई हैं।

वर्षों तक सैन्य मामलों में रुचि ना रखने के बाद पिछले कुछ वर्षों में जापान ने वापस सैन्य ताकत जुटानी शुरू की है। जापान ने साल 2022 से अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की शुरुआत की है। चीन की

ओर से खतरा इसकी अहम वजह रहा है। उसी साल प्रकाशित एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज में जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा के माहौल को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर और खतरनाक बताया था।

जापान को इन कोशिशों में अमेरिका का साथ मिलता रहा है। जापान अब पलटवार करने की क्षमता और हथियार वगैरह को लेकर नियम आसान बना रहा है। जापान, दक्षिण चीन सागर के इलाके में बसे देशों को फंडिंग और सैन्य सामान देने की शुरुआत भी कर चुका है। जापान की ओर से दी जा रही सैन्य मदद में निगरानी जहाज जैसे संसाधन हैं। इसके अलावा जापान ने जुलाई में फिलीपींस के साथ एक-दूसरे की धरती पर सैनिकों की तैनाती को लेकर भी समझौता किया था।

चीन सिर्फ दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के इलाके में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकतों में से एक माना जाता है। इसका करीब 700 सैन्य जहाजों वाला समुद्री बेड़ा काफी ताकतवर है। ऐसे में जापान का अगला लक्ष्य है, साल 2027 तक रक्षा संबंधी बजट को जीडीपी के दो फीसदी हिस्से तक लाना। इस बढ़े बजट का अच्छा-खासा हिस्सा जापान के सुदूर द्वीपों पर सुरक्षा स्थिति मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। अब यह जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा हैं।

चीन के सैन्य विमान की ओर से जापान में घुसपैठ का ताजा मामला अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के चीन पहुंचने से ठीक पहले हुआ है। सुलिवन, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात करने के लिए बीजिंग आए हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों को जलमार्गों के बारे में भी बात करनी है। ऐसे में कुछ जानकारों का मानना है कि चीन की ओर से यह घुसपैठ, अमेरिका को ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध बढ़ाने के खिलाफ संकेत देने की कोशिश है।

चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाता रहा है। इसकी प्रमुख वजह इस रास्ते से हर साल होने वाला हजारों अरब डॉलर का व्यापार है। व्यस्त व्यापारिक मार्ग होने के अलावा दक्षिणी चीन सागर में प्राकृतिक गैस और तेल का भी बड़ा भंडार है। अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, यहां तकरीबन 190 ट्रिलियन घन फीट गैस और 1,100 करोड़ बैरल तेल का भंडार होने का अनुमान है।

दक्षिण चीन सागर में रेयर अर्थ मिनरल का भी बड़ा भंडार है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों समेत कई विकसित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अहम हैं। चीन कहता है कि पूरा दक्षिण चीन सागर उसकी सीमा में आता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट फैसला दे चुका है कि बीजिंग के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि, चीन के इन दावों की वजह से उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया के साथ संघर्ष होता रहा है।

श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव: विक्रमसिंघे के सामने कई चुनौतियां

सीके/आरपी

गुरुवार 29 अगस्त को अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पैकेज को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत थी। 75 साल के विक्रमसिंघे ने कहा कि आईएमएफ के जिस 2.9 अरब डॉलर के पैकेज पर उन्होंने 2023 में समझौता करवाया था उसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत थी और देश को या तो उन सुधारों को लागू करना होगा या उसी कठिन परिस्थिति में फिर से पहुंच जाने के लिए तैयार रहना होगा। अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा, आईएमएफ और हमारे द्विपक्षीय करदाताओं से किए गए समझौतों को बदला नहीं जा सकता। कुछ उम्मीदवारों को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी।

विक्रमसिंघे के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं विपक्ष के नेता सजिथ प्रेमदासा (उम्र 57 साल) और मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके (55 साल) और दोनों ने आईएमएफ के साथ इन समझौतों को फिर से करने के लिए नए सिरे से बातचीत करने का वादा किया है। प्रेमदासा ने यह भी वादा किया है कि वो विक्रमसिंघे द्वारा दोगुना किए गए इनकम टैक्स में भी कटौती करेंगे। दिसानायके की पार्टी ने कहा है कि वो सरकारी कंपनियों के होने वाली निजीकरण को रोकेगी। प्रतिद्वंदियों के इन वादों के बीच विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी आईएमएफ के साथ इस बात पर सहमति बनी है कि अगले साल से मध्यम वर्ग और कम आय वाले वर्गों पर टैक्स के बोझ को कम किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। विक्रमसिंघे के दो सालों के कार्यकाल के दौरान महंगाई दर 70 प्रतिशत से नीचे गिर कर पांच प्रतिशत पर आ गई। ब्याज दरें भी नीचे आ गईं, रुपये की स्थिति बेहतर हुई और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा। लेकिन लोग ऊंची टैक्स दरों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं और बढ़े हुए खर्च से सभी प्रभावित हैं। लेकिन विक्रमसिंघे की चुनौती सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। प्रेमदासा और दिसानायके को मिला कर कुल 38 उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल हैं। राजपक्षे की पार्टी अभी भी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था। इसके अलावा विक्रमसिंघे की पिछले साल एक स्थानीय चुनाव करवाने से मन करने के लिए भी आलोचना हो रही है। उन्होंने उस समय कहा था कि देश के पास चुनाव करवाने के पैसे नहीं हैं। उनके यह फैसला अदालत में गया और पिछले हफ्ते ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो श्रीलंका मतदाता के मूलभूत अधिकार के उल्लंघन के दोषी हैं। अदालत ने आदेश दिया कि यह चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिसानायके के नेतृत्व में नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। यह गठबंधन मजदूर वर्ग का वोट जीतने की कोशिश कर रहा है और उस बदलाव को लाने का वादा कर रहा है जिसकी आर्थिक संकट के समय लाखों लोगों ने कामना की थी। दिसानायके ने बताया, हमारे देश के लोगों में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीद है। उन्हें बदलाव चाहिए था और हम वो बदलाव लाने वाले हैं। बाकी सभी उम्मीदवार उसी पुराने, असफल, पारंपरिक सिस्टम के एजेंट हैं।

पंचतत्वों पर आधारित खानपान रखे स्वस्थ

पंचतत्व अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमें अपने खानपान में प्रतिदिन इन पांचों तत्वों का भी सेवन करना चाहिए। ऐसा होने पर हम अधिकाधिक स्वस्थ व सक्रिय रह सकेंगे।

वायु - सांस के माध्यम से हर प्राणी वायु ग्रहण करता है। बाकी तत्वों को कुछ समय या कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है, पर वायु को नहीं। जो लोग अनशन या उपवास करते हैं, वे भी अन्न, फल, सब्जी या जल आदि छोड़ देते हैं, पर वायुसेवन नहीं। एक समय आहार लेने वाले संन्यासी भी वायुसेवन तो प्रतिक्षण करते ही हैं। अर्थात् पंचतत्व में से वायु प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

यह वायु व्यक्ति को शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप में पर्याप्त मात्रा में मिले, यह भी आवश्यक है। जो लोग बड़े शहरों में या उद्योगों के पास रहते हैं, उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती। इसीलिए इन दिनों नये-नये रोग लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो बड़े नगरों में शुद्ध ऑक्सीजन के बूथ खुलने लगे हैं, जहां पैसे देकर व्यक्ति दस-पन्द्रह मिनट शुद्ध प्राणवायु ले सकता है। जैसे आजकल हर व्यक्ति अपने साथ साफ पानी की बोतल रखने लगा है, लगता है कुछ समय बाद लोग प्राणवायु के छोटे सिलेंडर भी साथ लेकर चला करेंगे। ताजी और शुद्ध प्राणवायु प्राप्त करने की निःशुल्क विधि प्रातःकालीन भ्रमण है। सूर्योदय होने पर पेड़ों द्वारा रात में उत्सर्जित कार्बन डायआक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। ऐसे शीतल और शांत वातावरण में अकेले या सपरिवार घूमना शुद्ध वायु ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है।

केवल घूमना ही नहीं, तो इस समय कुछ आसन, व्यायाम और प्राणायाम करना भी बहुत लाभदायक है। सुबह की ही तरह शाम का भ्रमण भी बहुत लाभकारी है। इन दोनों समय पर दिन और रात का मिलन होता है। इसके सदुपयोग से हम अपने शरीर तथा मन को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों और युवाओं को तो शाम के समय पढ़ने की बजाय खेलना ही चाहिए।

चाहे कोई स्वयं वाहन न चलाता हो, पर प्रदूषित वायु सेवन करना तो उसकी भी मजबूरी ही है। इसलिए जहां सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का बहुत अच्छा होना जरूरी है, वहां दस-बीस कदम जाने के लिए वाहन निकालने की आदत भी छोड़नी होगी। पेड़ों को कटने से बचाकर तथा परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पेड़ लगाकर हम प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दे सकते हैं।

जल- वायु की ही तरह जल भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। किसी समय बहता पानी निर्मला कहकर नदियों का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता था, पर अब नगरों के सीवर, कारखानों के अपशिष्ट, समय-समय उसमें विसर्जित की जाने वाली रासायनिक रंगों से पुती मूर्तियां तथा अन्य कूड़े करकट के कारण नदियां आचमन योग्य भी नहीं रह गयी हैं। अब तो सब जगह कुछ घंटों के लिए सरकारी पानी मिलता है। वह कितना शुद्ध होता है, कहना कठिन है। पानी साफ और भरपूर मिले, इसके लिए निजी बोरिंग कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिनके लिए यह संभव नहीं है, उन्होंने भी घरों में फिल्टर लगा लिये हैं। इनसे एक लीटर पानी साफ होने के चक्कर में चार लीटर पानी नाली में बह जाता है। शहरीकरण का अर्थ ही है, बिजली और पानी का अत्यधिक प्रयोग। अतः जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

विद्वानों का मत है कि अगला विश्व युद्ध जल के कारण होगा। इसका सत्य तो भविष्य बताएगा पर नलों पर हर दिन डिब्बे और कनस्तर लिये लोगों को झगड़ते हुए कोई भी देख सकता है। मंगल आदि ग्रहों पर जाने वाले यान भी वहां सबसे पहले पानी की ही तलाश कर रहे हैं। इसके बाद भी लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। जो कार दो बाल्टी पानी में धोई जा सकती है, उसे दो हजार लीटर साफ पानी से धोते हुए लोग प्रायः मिल जाते हैं। हम वर्षा जल का संरक्षण कर तथा पानी को व्यर्थ न जाने देकर भी इस दिशा में अपना व्यक्तिगत सहयोग दे सकते हैं। हम साफ पानी पिएं, यह तो आवश्यक है ही पर कितना पिएं, इस बारे में अलग-अलग मत हैं। फिर भी एक व्यस्क व्यक्ति को दिन भर में आठ-दस गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। सुबह उठकर कुल्ला-मंजन के बाद तांबे के साफ पात्र में रखा पानी भरपेट पीना बहुत लाभ देता है। तांबा जल की अधिकांश अशुद्धियां दूर कर देता है। सर्दियों में पानी को गुनगुना कर लें, तो और अच्छा रहेगा।

आकाश- आकाश की पहचान खालीपन या शून्यता है। घटाकाश और मठाकाश जैसी कल्पनाएं इसी में से आई हैं। आकाश में कोई भी चीज फेकें, खाली होने के कारण वह मना नहीं करता। वायु और अंतरिक्ष यान इसीलिए आकाश में निर्द्वन्द उड़ते हैं। किसी पात्र के खाली होने का अर्थ है कि उसमें आकाश तत्व विद्यमान है पर जब उसमें कोई वस्तु डालते हैं, तो वह हट जाता है। ऐसी शून्यता हम अपने पेट को बिल्कुल खाली रखकर प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रातः शौचादि से निवृत्त होने के बाद लगभग दो घंटे तक पेट को अवकाश दें। इससे जहां भोजन पचाने वाली इंद्रियों को आराम तथा अपनी टूट-फूट ठीक करने का समय मिलेगा, वहां हमें आकाश तत्व भी प्राप्त होगा। व्रत और उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का अवसर कुछ अधिक समय तक प्रदान करते हैं। इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए पर इस नाम पर दिन में कई बार पेट में गरिष्ठ चीजें ठूंसते रहना शुद्ध पाखंड है।

पृथ्वी- पृथ्वी हमें अन्न, दाल और सब्जियां आदि देती है। अतः इनके सेवन से हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है पर इन्हें कच्चा नहीं खा सकते। इन्हें आग पर पकाकर तथा आवश्यकतानुसार कुछ अन्य मिर्च-मसाले डालकर प्रयोग किया जाता है। इनका सेवन कितना और कितनी बार करें, इसका कोई मापदंड नहीं है। शारीरिक परिश्रम करने वाले किसान या मजदूर तथा कार्यालय में बैठकर काम करने वाले की आवश्यकता अलग-अलग होगी। उन्हें उसी अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा न होने पर जहां एक ओर तोंद वाले, तो दूसरी ओर दुबले-पतले लोग सर्वत्र घूमते मिलते हैं।

अग्नि-
अग्नि का स्रोत सूर्य है। सर्दियों में तो सीधे धूप में लेटना या बैठकर काम करना अच्छा लगता है। गर्मियों में भी अपने काम के सिलसिले में घूमते-फिरते धूप लगती रहती है। इससे अग्नि तत्व अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग दिन भर वातानुकूलित वातावरण अर्थात् एसी वाले घर, कार्यालय और कार में रहते हैं, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए थोड़े से परिश्रम या मौसम बदलने मात्र से ही ये लोग बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। भीषण गर्मियों में जहां लू से बचना आवश्यक है, वहां धूप से डरना भी अनुचित है।

जहां तक खानपान की बात है, तो सूर्य की ऊर्जा से पके हुए फल और सलाद आदि के सेवन से अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है पर इनका सेवन सूर्यकाल में ही करना चाहिए। अर्थात् सूर्यास्त के बाद इन्हें खाना ठीक नहीं है। इसी तर्ज पर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पृथ्वी तत्व वाले जिन पदार्थों को खाने से पूर्व आग पर चढ़ाना पड़ता है, उन्हें सूर्य की उपस्थिति में नहीं खाना चाहिए। यद्यपि बहुत से लोग अपनी धार्मिक आस्था या वृद्धावस्था के कारण सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाते। उनका कहना है कि सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचनक्रिया मंद हो जाती है। अतः उस समय भारी भोजन ठीक नहीं है। विचार भिन्नता के कारण इस विषय को स्वतंत्र छोड़ देना ही उचित है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें समय-समय पर कुछ बुजुर्गों के मुंह से सुना है। इसमें से कुछ का प्रयोग करने से लाभ भी हुआ है। यद्यपि आज की भागदौड़ वाले जीवन में सब नियमों का पालन संभव नहीं होता। फिर भी जितना हो सके, उतना पालन करके देखें।

पेट दर्द के घरेलू उपचार

अधिकतर बीमारियों की वजह होती है असंयमित खान-पान। गलत खान-पान के कारण कभी-कभी पेट में दर्द होने लगता है। आमतौर पर पेट दर्द का एक मुख्य कारण अपच, मल सूखना, गैस बनना यानी वात प्रकोप होना और लगातार कब्ज बना रहना भी है। पेट दर्द को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं, जो दर्द तो दूर करते हैं, साथ ही साथ पेट की क्रियाओं को भी ठीक करते हैं।

- पेट दर्द मे हींग का प्रयोग लाभकारी होता है। 2 ग्राम हींग थोड़े पानी के साथ पीसकर पेस्ट बनाएं। नाभी पर और उसके आस-पास यह पेस्ट लगाएं।
-अजवाइन को तवे पर सेक लें और काले नमक के साथ पीसकर पाउडर बनाएं। 2-3 ग्राम गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से पेट का दर्द दूर होता है।
-जीरे को तवे पर सेकें और 2-3 ग्राम की मात्रा गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लें। इसे चबाकर खाने से भी लाभ होता है।
-पुदीने और नींबू का रस एक-एक चम्मच लें। अब इसमें आधा चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उपयोग करें। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, पेट दर्द में आराम मिलेगा।
-सूखी अदरक मुंह में रखकर चूसने से भी पेट दर्द में राहत मिलती है।
-बिना दूध की चाय पीने से भी कुछ लोग पेट दर्द में आराम महसूस करते हैं।
-अदरक का रस नाभी स्थल पर लगाने और हल्की मालिश करने से पेट दर्द में लाभ होता है।
-अगर पेट दर्द एसिडिटी से हो रहा हो तो पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर पीने से फायदा होता है।
-पेट दर्द निवारक चूर्ण बनाएं। इसके लिए भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सौंठ, लहसुन, धनिया, हींग, सूखी पुदीना पत्ती सबकी बराबर मात्रा लेकर बारीक चूर्ण बनाएं। इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मिलाएं। खाने के बाद एक चम्मच थोड़े से गर्म पानी के साथ लें। पेट दर्द में आशातीत लाभकारी है।
-एक चम्मच शुद्ध घी में हरे धनिये का रस मिलाकर लेने से पेट की व्याधि दूर होती है।
-अदरक का रस और अरंडी का तेल प्रत्येक एक-एक चम्मच मिलाकर दिन में 3 बार लेने से पेट दर्द दूर होता है।
-अदरक का रस एक चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच लेकर उसमें थोड़ी सी शक्कदर मिलाकर प्रयोग करें। पेट दर्द में लाभ होगा। दिन में 2-3 बार ले सकते हैं।
-अनार पेट दर्द मे फायदेमंद है। अनार के बीज निकालें। थोड़ी मात्रा में नमक और काली मिर्च का पाउडर डालें। और दिन में दो बार लेते रहें।
-मेथी के बीज पानी में भिगोएं। पीसकर पेस्ट बनाएं। और इस पेस्ट को 200 ग्राम दही में मिलाकर दिन में दो बार लेने से पेट के विकार नष्ट होते हैं।
-इसबगोल के बीज दूध में 4 घटे भिगोएं। रात को सोते समय लेते रहने से पेट में मरोड़ का दर्द और पेचिश ठीक होती है।
-सौंफ में पेट का दर्द दूर करने के गुण होते है। 15 ग्राम सौंफ रात भर एक गिलास पानी में भिगोएं। छानकर सुबह खाली पेट पीयें। बहुत गुणकारी उपचार है।
-आयुर्वेद के अनुसार हींग दर्द निवारक और पित्तवर्द्धक होती है। छाती और पेट दर्द में हींग का सेवन बेहद लाभकारी होता है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने पर एकदम थोड़ी सी हींग को एक चम्मच पानी में घोलकर पका लें। फिर बच्चे की नाभी के चारों लगा दें। कुछ देर बाद दर्द दूर हो जाता है।
-नींबू के रस में काला नमक, जीरा, अजवायन चूर्ण मिलाकर दिन में तीन बार पीने से पेट दर्द से आराम मिलता है।

आंखों पर दें ध्यान

आंखें अनमोल हैं, इसलिए इनकी सेहत का बदलते मौसम के अनुसार ध्यान रखना आवश्यक है

- आंखों में सूखापन की समस्या सर्दियों में बढ़ सकती है। सूखेपन से बचाव के लिए डॉक्टर के परामर्श से आर्टीफिशियल टीयर ड्रॉप का इस्तेमाल करें।
- इस मौसम में एलर्जी की शिकायत भी सभव है। इससे बचने के लिए दिन में दो बार आंखों को साफ पानी से धोएं। इन्हें मलें या रगड़ें नहीं।
- चेहरे के साथ आंख के आसपास व पलक की त्वचा को सूखेपन से बचाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी मॉइश्चराइजर या कोल्ड क्रीम आंख के अंदर न जाए।
- काला चश्मा लगाकर ही धूप में बैठें।
- नेत्रों को चश्मे के जरिये ठंडी हवाओं से बचाएं।

मुझे नींद नहीं आती, आपने अक्सर लोगों को यह शिकायत करते सुना होगा। नींद एक जैविक प्रक्रिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद बहुत ही जरूरी है। पर्याप्त नींद नहीं लेने से हमारी कार्यक्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिद्रा के शिकार लोगों को अक्सर दिन में इधर-उधर झपकियां लेते देखा जा सकता है।

होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं
अनिद्रा के रोगी

अनिद्रा आजकल एक महामारी की तरह फैलती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक आज विश्व में हर पांचवां व्यक्ति अनिद्रा का शिकार है। अनिद्रा का अर्थ है नींद में व्यवधान, नींद उचटना या कम नींद आना। यह दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की अनिद्रा का संबंध उन लोगों से जिन्होंने कभी अच्छी, चैन की नींद का आनंद नहीं लिया हो तथा ये लोग तनाव, घबराहट या अन्य किसी असहनीय पीड़ा से पीड़ित न हो। पहली प्रकार की अनिद्रा से पीड़ित लोगों की नाड़ी की गति तेज तथा शरीर का तापमान अधिक होता है। इनकी बाह्य धमनियां प्रायः संकुचित होती हैं। ये लोग प्रायः हिलते-डुलते रहते हैं। दूसरे प्रकार की अनिद्रा का संबंध उन लोगों की अनिद्रा से है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जैसे पेट में दर्द, पैरों में बेचैनी, थकान, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द आदि। इन बीमारियों से नींद की प्रारंभिक अवस्था में बाधा पहुंचती है।

दूसरे प्रकार की अनिद्रा साइकेट्रीक, साइकोसिस तथा साइकोन्यूरोसिस के मरीजों में आमतौर पर देखी जा सकती है। डर तथा चिंता भी अनिद्रा के कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन तथा मेनियक डिप्रेशन से भी अनिद्रा की शिकायत हो सकती है इससे सोने पर एक बार तो नींद आ जाती है परन्तु सुबह जल्दी आंख खुल जाती है तथा बाद में रोगी सो नहीं पाता। सन्निपात तथा कोई काल्पनिक डर भी अनिद्रा के कारण हो सकते हैं।

चिकित्सा की होम्योपैथिक शाखा के अंतर्गत अनेक ऐसी दवाईयां हैं जिनका प्रयोग अनिद्रा के उपचार के लिए किया जाता है। मरीज के लक्षणों के आधार पर कोई भी दवा उसे दी जा सकती है।

आर्सेनिक एलबम 30- यह दवा उन मरीजों को दी जाती है जो किसी मानसिक बेचैनी के कारण करवटें बदलते रहते हैं। वह शारीरिक रूप से इतना कमजोर होता है कि उसका चलना-फिरना भी मुश्किल होता है। मरीज को निरंतर मृत्यु का भय बना रहता है। वह इलाज के प्रति निराश हो चुका होता है। ऐसे रोगी को बार-बार थोड़े पानी की प्यास लगती रहती है।

केनाबिस इंडिका 30- यह उन रोगियों के लिए उपयुक्त होती है जो भय, भ्रांति तथा मानसिक दुर्बलता के शिकार होते हैं। ऐसे रोगी अक्सर मरे हुए लोगों को सपने में देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह पागल हो जाएंगे। ऐसा रोगी लगातार बोलता रहता है और सिर हिलाता रहता है। अक्सर बोलते-बोलते वह यह भी भूल जाता है कि उसे आगे क्या बोलना है। विनम्र स्वभाव का व्यक्ति यदि उद्दण्ड स्वभाव हो जाए तो उसे यह दवा दी जाती है।

हायोसाइमस नाइगर 200- इसमें मरीज बहुत बातूनी और ईर्ष्यालु होता है। इस प्रकार का रोगी बहुत डरता है। उसे हर बात में डर लगता है जैसे अकेले रहने का डर, विष खिलाने का डर, किसी षड़यंत्र का डर आदि। बच्चों में नींद न आना, नींद आते ही डर जाना, बिस्तर से निकलने या भागने की कोशिश करना जैसे लक्षण होने पर यह दवा दी जाती है।

कैफिया क्रूडा 200- यह दवा उन रोगियों के लिए उचित है जिन्हें रात को नींद नहीं आती। वे अक्सर भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। ऐसे रोगी अचानक ही हंसने या रोने लगते हैं ऐसे रोगियों को बहुत अधिक चिंता, बातचीत या मानसिक परिश्रम करने में सिर में तेज दर्द होता है।

एकोनाइटम नैपेलस 30- इसमें रोगी अक्सर बैचेन रहता है जिससे उसे नींद नहीं आती। उसे इतना डर लगता है कि वह बेहोश भी हो जाता है। स्थिति गिंभीर होने पर रोगी को मरने का डर लगने लगता है। रोगी अक्सर डर के कारण घर से नहीं निकलता, भीड़भाड़ वाली जगहों से भी बचता है। उसे बार-बार पानी की प्यास भी लगती है।

इग्नेशिया अमारा 200- यह दवा उन रोगियों को दी जाती है जो शोक, भय या दुख की वजह से एकाएक बेहोश हो जाते हैं। उसे तम्बाकू या धुंआ सहन नहीं होता। उसके सिर में भी दर्द होता है। प्रेम या काम में निराशा से उत्पन्न अनिद्रा के लिए भी यही दवा कारगर होती है।

पोर्स फ्लोरा इन्कार्नेटा (क्यू)- वृद्धों तथा बच्चों में अनिद्रा दूर करने के लिए यह दवा कारगर सिद्ध होती है। यह दवा उन रोगियों की दी जाती है। जिन्हें तनाव और अत्यधिक मानसिक कार्य के कारण नींद नहीं आ पाती या सिर दर्द और आंखों में दर्द के कारण नींद नहीं आती।

किसी भी दवा के चुनाव से पहले रोगी के लक्षण पहचानना जरूरी होता है तथा किसी भी दवा के प्रयोग से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी जरूरी होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ममता बनर्जी ने फिर लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने पहले भी बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पत्र में बनर्जी ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट पोक्सो अदालतों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित अदालतें पूरे राज्य में पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर काम कर रही हैं, मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से अदालतों के हाथों में है। अपने नवीनतम पत्र में, जिसकी एक प्रति उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की थी, बनर्जी ने केंद्र सरकार से देश में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून लाने का आग्रह किया। हालाँकि, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है, जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है।

कोलकाता मामले में बंगाल पर राजनाथ सिंह का कटाक्ष

तिरुवनंतपुरम। कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन कई राज्य इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या की पृष्ठभूमि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बात की। रक्षा मंत्री ने इस घटना को दिल दहला देने वाला और शर्मनाक बताया, हालांकि उन्होंने बंगाल सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराने से परहेज किया, जो इस मामले को दबाने के आरोपों से घिरी हुई है। हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन कई राज्य इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं।

जमात-ए-इस्लामी के पक्ष में खड़ीं हुईं मबबूबा मुफ्ती

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने जमात-ए-इस्लामी के लिए चुनाव को हराम बना दिया था। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, महबूबा ने कहा कि 1987 में, जब जमात-ए-इस्लामी और अन्य समूहों ने चुनाव में भाग लेने की कोशिश की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत उभरे। उन्होंने कहा कि पहले उनके लिए चुनाव हराम था, अब हलाल हो गया है। लेकिन पूरी तरह से, यह उनका फैसला है। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर जमात-ए-इस्लामी चुनाव लड़ना चाहती है तो यह अच्छी बात है। सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए, उनकी सभी संस्थाएं, संपत्तियां जो आपने फ्रीज की हैं, जब्त की हैं, उन्हें डी-फ्रोजन किया जाना चाहिए, उन्हें वापस किया जाना चाहिए।

विधायक रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की

रांची। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामदास सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि चंपई सोरेन, जिन्होंने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया था, वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कुछ समय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। रामदास सोरेन ने 2009 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीत हासिल की थी और वह झामुमो की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं। वह झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे। झारखंड आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोल्हान क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है।

अजित पवार ने राजकोट किले का किया दौरा

मुंबई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर राजनीतिक तूफान के बीच, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को सिंधुदुर्ग जिले के मालवन का दौरा किया और इस सप्ताह की शुरुआत में गिरी 35 फुट ऊंची संरचना को हुए नुकसान का आकलन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के साथ, पवार ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और मूर्ति के ढहने का कारण निर्धारित करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। दौरे के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, पवार ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई दुखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं और सभी को उनके इतिहास पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैठकें की हैं। स्मारक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

पीएम मोदी ने वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी, 1560 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने यहां 76,000 करोड़ रुपये की वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इससे पहले उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित किया।

वधावन बंदरगाह की परियोजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है। पालघर जिले के दहानु शहर के पास स्थित वधावन बंदरगाह भारत में गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह बंदरगाह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से लैस होगा। इसके अलावा 360 करोड़ रुपये की लागत से मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए संचार, सहायता प्रणाली की भी

शुरुआत से भी लोगों काफी फायदा होगा। इस परियोजना के तहत, 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत और मोटर चालित नौकाओं पर चरणबद्ध तरीके से एक लाख ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाएंगे।

इससे पहले महाराष्ट्र दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, %मैं 30 अगस्त को महाराष्ट्र के लोगों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं। मैं मुंबई और पालघर में कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। मुंबई में, मैं सुबह लगभग 11 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लूंगा। यह मंच भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। फिनटेक की दुनिया में और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के बाद, मैं वाधवन बंदरगाह परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पालघर में रहूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने सिर झुकाकर मांगी माफी

मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। आज मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप-शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। वे लोग वीर सावरकर को गालियां देने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। उनको पाश्चाताप नहीं होता है... महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान गई है।

मोदी ने कहा कि जब 2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ के किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ कर प्रार्थना की और राष्ट्रसेवा की एक नई यात्रा आरंभ की थी। उन्होंने कहा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवता मानते हैं और इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है, मैं सिर झुकाकर उनसे माफी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग हैं। हमारे लिए हमारे देवता से बड़ा कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवता मानते हैं और इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है, मैं सिर झुकाकर उनसे माफी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग हैं। हमारे लिए हमारे देवता से बड़ा कुछ नहीं है। मोदी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के पास विकास के लिए सामर्थ्य भी है और जरूरी संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है और इन तटों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी हैं। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र और देश को मिले... इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दो-तीन दिन पहले ही दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है। यानि, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये छत्रपति शिवाजी के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति यात्रा में आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत की प्रगति यात्रा में आज एक ऐतिहासिक दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, पिछले 10 वर्षों में हमने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए लगातार बड़े फैसले लिए हैं।

चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से आया बुलावा

■ पत्नी पायल संग मध्यस्थता केंद्र में पेश होने का दिया निर्देश

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 अगस्त) को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए पेश होने का निर्देश दिया। उमर ने सुप्रीम कोट में तलाक की याचिका दायर कर कहा था कि वह और उनकी पत्नी पिछले 15 साल से अलग रह रहे हैं। दोनों ने 1 सितंबर 1994 को शादी कर ली और 2009 से अलग रह रहे हैं।

उनके दो बेटे भी हैं। उमर ने शुरू में परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, 30 अगस्त, 2016 को कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह यह साबित करने में विफल रहे कि उनकी शादी को अपूरणीय क्षति हुई थी। इसके बाद उमर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2023 में, जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उन्हें समाधान तक पहुंचने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। उमर अब्दुल्ला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर नोटिस जारी किया था और पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा था।

पायल अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने आज अदालत को सूचित किया कि कम से कम एक बार मध्यस्थता का प्रयास किया जाना चाहिए। सिब्बल ने मध्यस्थता में भाग लेने पर सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य मामले को सुलझाना होगा, जरूरी नहीं कि सुलह हो।

यूपी में लाल टोपी को लेकर घमासान हुआ तेज

■ सीएम योगी के बयान पर भड़के अखिलेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बर पलटवार का दौर लगातार जारी रहता है। हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि लाल रंग की टोपी पहनने वालों के काले कारनामे सभी को पता है। सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि योगी ने कहा कि आज विकास और सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए, कानून-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह उत्तर प्रदेश तय करता है। इसी पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सदमा लग जाता है तो लोग भी कुछ कहते हैं। लाल रंग को समझना होगा। यह लाल रंग क्रांति का है, मेल-मिलाप का है। लाल रंग भाव का है। हमारे मुख्यमंत्री भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। ये टोपी उन लोगों के काम भी आ सकती है जो गंजे हों। उन्होंने कहा कि हमारा लाल रंग खुशी, त्यौहार का है... आखिर इस रंग से नाराजगी क्या है? योगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि रंग अच्छा बुरा नहीं होता, नजरिया अच्छा बुरा होता है। अखिलेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, जनता की संसद का प्रश्नकाल। प्रश्न-लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? दो-दो बिंदुओं में अंकित करें। उन्होंने लिखा, उत्तर-रंगों का मन-मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है, तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है, तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अखिलेश ने लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम-मिलन, मेल-मिलाप का अभाव होता है, वे अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है, लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है, वे लाल रंग को चुनौती मानते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

बारिश से पाकिस्तान-बांग्लादेश के पहले दिन का मैच रद्द

रावलपिंडी। टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम रावलपिंडी में दूसरे और अंतिम टेस्ट में बांग्लादेश से भिड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरे मैच के पहले दिन ही बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और मैच शुरू होने से पहले रद्द हो गया। दरअसल, 30 अगस्त को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे मैच का पहला दिन रद्द कर दिया गया। पूरे दिन खराब मौसम के कारण मैच अधिकारियों को दिन का खेल रद्द करना पड़ा, जिससे फैंस और खिलाड़ियों दोनों को निराशा हुई। रावलपिंडी में भारी बारिश के कारण आउटफील्ड पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिससे खेल शुरू होना असंभव हो गया। अगर बारिश रुक भी जाए, तो भी मैदान की स्थिति क्रिकेट के लिए अनुपयुक्त रहेगी, क्योंकि ग्राउंड्समैन को पिच और आउटफील्ड तैयार करने में काफी समय लगेगा, इस स्थिति को देखते हुए मैच रद्द करना ही उचित समझा गया। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को मिली हार के बाद मैनेजमेंट को कुछ कठोर चयन निर्णय लेने पड़े। मार्की पेसर शाहीन शाह अफरीदी अपने बेटे के जन्म के कारण दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से किसी एक के उनकी जगह लेने की संभावना है।

बांग्लादेश टीम: शादमान इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, शोरफुल इस्लाम, नाहिद राणा, महमुदुल हसन जॉय , खालिद अहमद, नईम हसन, तस्कीन अहमद, तैजुल इस्लाम।

पाकिस्तान टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद , मोहम्मद अली, मीर हमजा, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद हुरैरा, आमेर जमाल।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

12वें दिन भी बढ़त पर बंद हुआ निफ्टी, सेंसेक्स 82,300 के पार

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। इंट्रा डे ट्रेड में लगातार तीसरे दिन निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई दर्ज किया तो सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा। 50 शेयरों वाला एनएसई बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 25,268.35 का रिकॉर्ड हाई और सेंसेक्स 82,637.03 के हाई लेवल पर पहुंचा। शेयर बाजार की क्लोजिंग की बात की जाए तो आज लगातार 12वें दिन निफ्टी-50 बढ़त दर्ज करते हुए 25,235.90 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 0.33% या 83.95 अंकों की तेजी आई। जबकि, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 0.28% या 231.16 अंकों की बढ़त के साथ लगातार नौंवे दिन हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 82,365.77 के लेवल पर क्लोज हुआ।

सिंगापुर एयरलाइंस को मिली एफडीआई की मंजूरी

नई दिल्ली। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा-एयर इंडिया के बीच विलय समझौते के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौते के तहत 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी। एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास है और विस्तारा का स्वामित्व टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों के पास है और दोनों की इसमें 51:49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। शुक्रवार को सिंगापुर एयरलाइंस ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में एक नियामक फाइलिंग में बताया कि उसे प्रस्तावित विलय के हिस्से के रूप में विस्तारित एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि प्रस्तावित विलय के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

फिनटेक सेक्टर के विकास पर सरकार का जोर

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर विभिन्न उपाय कर रही है। पिछले 10 वर्षों में इस सेक्टर में 31 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है। फिनटेक स्टार्टअप में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एंजल टैक्स को समाप्त करना भी इस सेक्टर के विकास की दिशा में उठाया गया एक कदम है। एंजल कर (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती हैज्यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। प्रधानमंत्री ने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी को रोकने और लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाने के लिए और अधिक उपाय करने के लिए भी कहा। फिनटेक सेक्टर ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने, ऋण तक पहुंच को आसान तथा समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय कंपनियों को आपस में भी सहयोग करने जरूरत

नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों से एक-दूसरे का समर्थन करने और सामान खरीदने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे उन्हें दीर्घावधि में लाभ होगा तथा वैश्विक महामारी जैसी किसी भी बाधा से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को देश में हाल ही में स्वीकृत 12 औद्योगिक शहरों (टाउनशिप) में कारोबारी अवसर तलाशने का सुझाव भी दिया, क्योंकि इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोयल ने उद्योग जगत के लोगों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा, '' हमें भारत को एक ब्रांड बनाने की जरूरत है। हमें एक-दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। उद्योग जगत को न केवल अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ, बल्कि एक-दूसरे के साथ भी भागीदार बनने की जरूरत है।

कारोबार में अनुपालन नहीं विश्वास बहाली बेहतर

अजय कुमार

कोई समाज कितना विकसित है उसका पता इस बात से चलता है कि सरकार अपने नागरिकों, कारोबार और संस्थाओं में कितना भरोसा करती है। यह भरोसा या उसकी कमी सरकार के तंत्र और प्रक्रियाओं में भी दिखाई देती है। विकसित देशों की सरकारों के भीतर विकासशील देशों की तुलना में विश्वास का स्तर प्रायः अधिक दिखता है। किंतु इस बात का अध्ययन यदा-कदा ही किया जाता है।

किसी भी कागजी कामकाज के लिए दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया जाना विश्वास की इसी कमी की ओर इशारा करता है। कागजों से काम करने वाले किसी भी अफसरशाही तंत्र में सत्यापन की यह अनिवार्यता खर्च और तामझाम दोनों बढ़ा देती है। छोटे और गरीब वर्ग के लिए यह पूरी प्रक्रिया खास तौर पर जटिल हो जाती है। सरकार और जनता सहित विभिन्न समूहों के बीच अविश्वास का दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब कोई आवेदन करने पर अक्सर अनावश्यक जानकारी मांगी जाती है।

यह जानकारी यही मानकर मांगी जाती है कि आवेदन करने वाला कुछ न कुछ छिपा रहा होगा। विभिन्न स्तरों पर सख्त निगरानी से यह भी लगता है कि कर्मचारियों की ईमानदारी और उनकी कुशलता पर संदेह या अविश्वास है। अपेक्षित परिणामों पर अधिक ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर जोर इस पूर्वग्रह का संकेत है कि कोई व्यक्ति बिना सख्त निर्देश और निगरानी के पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम नहीं कर सकता।

विश्वास स्वस्थ परंपरा ही नहीं है बल्कि इसके पीछे आर्थिक तर्क भी काम करता है। यहां हर किसी को नैतिक रूप से खरा मानने की बात नहीं है बल्कि यह समझने और स्वीकार करने की बात है कि पूर्ण अनुपालन

सुनिश्चित करने पर आने वाला खर्च कुछ उल्लंघनों की तुलना में अधिक है। विश्वास से क्षमता बढ़ती है, नियामकीय दबाव कम होता है और सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां सबल होती हैं।

विश्वास पर आधारित तंत्र में कागजी तामझाम, निगरानी के विभिन्न स्तर और लालफीताशाही कम हो जाती है, जिससे प्रशासनिक व्यय भी कम हो सकता है। इससे सरकार को वृद्धि को गति देने तथा नवाचार में निवेश करने के अधिक अवसर मिलेंगे। भरोसा दिखाया जाए तो निष्पक्ष तथा पारदर्शी तंत्र के जरिये लोग खुद ही अनुपालन करते हैं, सोच समझकर जोखिम लेते हैं, नवाचार बढ़ता है और नियम-कायदों का पालन किया जाता है।

अंग्रेजी हुकूमत के कई तौर-तरीके अभी तक चले आ रहे हैं। उनमें एक था प्रशासनिक और प्रशासन तंत्र में अविश्वास की भावना। अंग्रेजी हुकूमत स्थानीय विरोध को दबाने और अपना वर्चस्व कामय रखने के लिए सबको संदेह की निगाह से देखती थी और उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए हथकंडे अपनाती थी। यह अविश्वास उनके शासन, उनकी कार्य प्रणाली में भी दिखता था, जैसे राजपत्रित अधिकारी (जो अक्सर अंग्रेज होते थे) से सत्यापन की शर्त। आजादी के बाद भी भारत के कानून एवं प्रक्रियाएं अंग्रेजी तंत्र पर ही आधारित रहे और अविश्वास की मानसिकता हर स्तर पर बढ़ती गई।

दो शताब्दियों की अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हम स्वयं अविश्वास के आदी हो चुके थे, जो नए निजाम में और भी बढ़ता गया। नतीजतन पेचीदा नियामकीय व्यवस्था, कागजी औपचारिकताओं का झमेला और कई स्तरों पर नजर रखने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें आंतरिक एवं बाहरी ऑडिट, निगरानी प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, संसदीय समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त, न्यायिक इकाइयां, क्षेत्रवार नियामक, सूचना का अधिकार कानून और न जाने क्या क्या शामिल है। इनका उद्देश्य जवाबदेही पक्की करना है मगर असल में ये कर्मचारियों पर और निगरानी तंत्र पर भी गहरे अविश्वास की तरफ इशारा करते हैं। इसी अविश्वास ने परिणामों के बजाय अनावश्यक औचारिकताओं को प्राथमिकता देने की सोच गहरी कर दी है।

संक्षिप्त समाचार

राज्य के तीन प्रमुख शहरों में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो

रायपुर। छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू होगी। यह स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। राज्य के अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी मिली है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस नए एफएम रेडियो स्टेशन के आगमन से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलेगा। यह कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को सशक्त करेगा।

मुख्यमंत्री से चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज कवर्धा राज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक केंद्रीय अधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय को चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष समाज का केंद्रीय अधिवेशन कबीरधाम जिले में 14 व 15 सितम्बर को आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के सदस्यों को केंद्रीय अधिवेशन में आमन्त्रण के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद चन्द्राकर, मोतीराम चन्द्रवंशी, अजीत चन्द्रवंशी, कैलाश चन्द्रवंशी, राजेन्द्र चन्द्रवंशी, दिनेश चन्द्रवंशी, रामविलास चन्द्रवंशी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

ग्राम हर्राडीह में लगाया नया ट्रांसफार्मर, ग्रामवासियों ने सीएम को दिया धन्यवाद

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप गांव हो या शहर सभी जगह बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित हो इसके लिए के विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन बिछाने के साथ ही समस्या आने पर तत्काल ट्रांसफॉर्मर, केबल और ग्रिप चेंज का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम हर्राडीह में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी। इसके समाधान के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन किया था। कैंप कार्यालय के निर्देश पर तत्काल यहां पर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है।

हैदराबाद-रक्सौल-सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 31 दिसंबर तक

रायपुर। रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली 07051/07052 हैदराबाद-रक्सौल-सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा दिनांक 28 सितम्बर, 2024 तक चल रही है। इस गाड़ी के परिचालन में विस्तार कर 31 दिसम्बर, तक किया गया है। यह गाड़ी 07051 हैदराबाद –रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को हैदराबाद से 12 अक्टूबर, 2024 से 28 दिसम्बर तक चलेगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी 07052 रक्सौल-सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 15 अक्टूबर, से 31 दिसम्बर, तक चलेगी। इस गाड़ी में 06 एसी थ्री, 02 एसी टू टायर, 01 एसी प्रथम कम एसी टू टायर, 10 स्लीपर, 02 सामान्य एवं 02 एसएलआर सहित कुल 23 कोच रहेंगे। रेलवे के द्वारा सिकंदराबाद-रक्सौल के मध्य 30 सितम्बर, तक चल रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार 2 जनवरी, तक किया गया है। यह गाड़ी प्रत्येक सोमवार को सिकंदराबाद से चलने वाली 07005 सिकंदराबाद-रक्सौल स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार 7 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक किया गया। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से चलने वाली 07006 रक्सौल-सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार 10 अक्टूबर,तक किया गया। इस गाड़ी में 02 एसएलआर, 04 सामान्य, 08 स्लीपर, 05 एसी थ्री, 02एसी टू, 01 एसी टू कम एसी थ्री सहित कुल 22 कोच के साथ रवाना होगी।

होटल पिकाडली से 9 जुआरी गिरफ्तार

रायपुर। होटल बेबीलॉन कैपिटल के बाद होटल पिकाडली में जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को सरस्वती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5, 13 का अपराध दर्ज किया है। मुखबीर की सूचना पर क्राइम यूनिट और थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल पिकाडिली के कमरा नंबर 311 में दबिश दी। वहां जुआ खेलते 9 जुआरियों को पकड़ा। बेबीलोन कैपिटल मामले में हुई किरकिरी के बाद पुलिस ने कल पकड़ाए सभी जुआरियों के नाम जारी किया है। इनमें संजय तखतानी, प्रभात मलंग, राजेश मनधानी, सुनील पंजवानी, तरुण (पुलिस ने इसका सरनेम नहीं बताया) अमित जैन, दिनेश मोटवानी, राकेश इडवानी, मनोहर मंधानी शामिल हैं। इनसे 4,07,000 रूपये एवं ताशपत्ती जप्त किए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे सदस्यता अभियान की शुरुआत

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान के लिए प्रभारियों की घोषणा की, पिछड़ा वर्ग के सभी सांसदों व विधायकों का होगा सम्मान

रायपुर। भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किया जा रहा है। 3 सितंबर को सुबह 11:00 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे होंगे। अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद के. लक्ष्मण, प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता उपस्थित रहेंगे।

भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इसी मंच से सदस्यता लेकर करेंगे। सम्मान समारोह में पिछड़ा वर्ग के समस्त कैबिनेट मंत्रियों सांसदों और विधायकों का सम्मान विशेष रूप से किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के तैयारी को लेकर प्रदेश भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रभारी व प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक ली, जहां भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षों से अधिक से अधिक संख्या में उक्त कार्यक्रम में आने के लिए निर्देशित किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से जिला पदाधिकारी व प्रदेश के 405 मंडल के पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया।

इस दौरान भाजपा प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश

महामंत्री पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु साहू, खिलावन साहू, अंबिका चंद्रवंशी, प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा, देवव्रत साहू, हीरोलाल सिन्हा, प्रदेश मीडिया प्रभारी छगन साहू, सहप्रभारी श्रवण यदु, सोशल मीडिया प्रभारी नरेंद्र निर्मलकर, सह प्रभारी तामेश्वर साहू, कार्यालय सह प्रभारी भगवान यादव सहित प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष गण विशेष रूप से उपस्थित थे।

इसके पूर्व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर के द्वारा कुछ दिनों पूर्व में की गई आवश्यक बैठक में आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति की गई। जिसमें रायपुर शहर जिला के लिए प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा, रायपुर ग्रामीण जिला के लिए देवव्रत साहू, बलौदा बाजार जिला के लिए भूपेंद्र सेन, जिला गरियाबंद भगवान यादव, जिला महासमुंद प्रकाश चंद्राकर, जिला धमतरी छगन साहू, भिलाई शांतनु साहू, जिला दुर्ग होरी लाल सिन्हा, जिला बेमेतरा अम्बिका चंद्रवंशी, जिला बालोद खिलावान साहू, जिला राजनांदगांव श्रीमती तुलसी साहू, जिला मोहला मानपुर चौकी रमेश सोनवानी, जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई आशीष कुमार साहू, जिला कवर्धा श्रीमती सुमन कनोजिया, जिला कांकेर भूपेंद्र चंद्राकर, जिला कोंडागांव टकेश्वर जैन, जिला नारायणपुर निर्देश दिवान, जिला बस्तर दिगंबर राव, जिला दंतेवडा अभिमन्यु सोनी, जिला सुकमा श्री हरि यादव, जिला बीजापुर श्रवण यदु, जिला बिलासपुर डा खिलावान साहू, जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही सुश्री सुनीता मानिकपुरी, जिला मुंगेली राजेश ताम्रकार, जिला शक्ति नरेंद्र साहू, जिला जांजगीर चापा सुश्री ऋतु चौरासिया, जिला कोरबा छगन साहू, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ कामता पटेल, जिला रायगढ़ तामेस्वर साहू, जिला जशपुर चुरामणि निर्मलकर, जिला सरगुजा मनोज गुप्ता, जिला सूरजपुर नरेन्द्र निर्मलकर, जिला बलरामपुर हरीश कटघरे, जिला महेन्द्रगढ़ चिरमिरी मोहन ऊपारकर, जिला कोरिया उपेंद्र गुप्ता बनाए गए हैं।

नक्सल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेगा 0% ब्याज पर लोन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा। दो लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बिना ब्याज के चार लाख तक का लोन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा।

राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित लोन मिलेगा। वहीं शेष जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसमें डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक छात्रों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय दो लाख से कम है, उनको मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन की ओर से सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।

इन्हें बिना ब्याज का लोन

राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

नियम और शर्तें

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित और सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये दो लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

चार लाख तक मिलेगा लोन

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये चार लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप आउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ

योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, बी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉडर्न आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट https://cgdteraipur.cgstate.gov.in/en/directorate पर अधिक जानकारी ले सकते हैं।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ को भी शामिल करने चेंबर ने की पीयूष गोयल से मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर ने पत्र के माध्यम से केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित करने हेतु निवेदन किया।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से बताया कि भारत को वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने के परिकल्पना को पूर्ण करेगा। पारवानी ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से निवेदन किया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ को भी शामिल करते हुए छत्तीसगढ़ में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना की जाए।

पारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ अपने भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक खनिज संपदा जैसे-लौह अयस्क, कोयला, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि से परिपूर्ण तथा विशाल जनशक्ति होने के कारण नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भारत को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करते हुए एनआईसीडीपी आर्बटन के लिये तत्काल उपलब्ध उन्नत विकसित भूमि प्रदान करेगा जिससे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये विनिर्माण इकाईयां स्थापित करना आसान हो जायेगा। छत्तीसगढ़ में अनेक संभावनाएँ हैं तथा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त समस्त संसाधन यहां प्रचुर मात्रा में प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बनने से उत्पादकता में वृद्धि होगी, बड़ी मात्रा में नवीन रोजगारों का सृजन होगा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के व्यापक उद्देश्य को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर नियद नेल्लानार क्षेत्रों में बुनियादि सुविधाओं की मिल रही सौगात

कावड़गांव, हिरोली सहित एक दर्जन गावों में आवागमन की सुविधा का हुआ विस्तार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर नियद नेल्लानार क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के नियद नेल्लानार आपका अच्छा गांव योजना के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

नियद नेल्लानार योजना के तहत सुरक्षा कैम्प के 5 किलोमीटर परिधि के गांवो में सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का विस्तार तीव्र गति से किया जा रहा है। शासन के इस महत्वाकांक्षी योजना से अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मुख्यधारा से जुड़कर यहां के ग्रामीण स्वयं के एवं अपने आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए प्रफुल्लित नजर आ रहे है।

स्थानीय कलेक्टर के मार्ग दर्शन में गत दिवस अति सुदूर क्षेत्र कांवडगांव, हिरोली, पुसनार, गंगालूर, चेरपाल, पदेड़ा, रेगडगुट्टा जैसे गांवों के ग्रामीणों को सुगमतापूर्वक जिला मुख्यालय पहुंचाने हेतु जनसुविधा बस को हरीझंडी दिखाकर

रवाना किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा हमारी कल्याण के लिए बनायी गई योजनाओं का अब समय पर क्रियान्वयन हो रहा है जिसका लाभ हम सबको मिलने लगा है। आवागमन की सुविधा के विस्तार होने से अब हम क्षेत्र वासी लाभान्वित होंगे।

देखो अपना देश अभियान में वोट कर अपने राज्य के गंतव्यों को बनाएं राष्ट्रीय धरोहर

छत्तीसगढ़ सरकार की अपील, देखो अपना देश अभियान में हिस्सा लें

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देशअभियान में सक्रिय भागीदारी करें। इस अभियान के तहत देशभर के नागरिकों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत गंतव्यों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह एक सुनहरा अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों को पूरे देश में पहचान दिलाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट https://forms.gle/ANvrFcQqxg55EkSw7 का उपयोग करना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ के उन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं, जिन्हें वे राज्य और देश का गौरव मानते हैं। राज्य सरकार ने भी सभी से आग्रह किया है कि वे इस लिंक को अपने सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले सकें। इस अभियान में वोट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। इसके बाद, चुने गए गंतव्यों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और यह अवसर हमें अपनी धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देशभर में फैलाने का मौका देता है।

पश्चिमी व मध्यवर्ती तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन पणजी गोवा में सम्पन्न

■ मंत्री कश्यप सम्मेलन में शामिल हुए और राज्य की आगामी 5 वर्षों की योजनाओं से अवगत कराया

रायपुर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में पश्चिमी और मध्यवर्ती राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार और नए आयाम जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों से सहयोग और समर्थन का आह्वान किया।

पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गोवा में पश्चिमी तथा मध्यवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ताकि पर्यटन क्षेत्र के लिए संकल्पना निर्माण तथा विचार-विमर्श किया जा सके और एक साझा विजन तैयार किया जा सके। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास, वैकल्पिक गंतव्यों के विकास, मार्केटिंग और संवर्धन,

पर्यटन क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्वच्छता, व्यवसाय करने की सुविधा और सुगमता में सुधार के साथ-साथ पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने संबंधी उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों को साझा करने पर फोकस किया गया। सम्मेलन में राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्र, वैकल्पिक गंतव्य, मार्केटिंग और संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता और निजी निवेश तथा स्वच्छता तथा पर्यटक सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया।

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की, साथ ही विकास की राह में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्री श्री कश्यप ने केंद्र से समर्थन और संसाधनों की मांग की ताकि छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके। मंत्री श्री कश्यप ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्यप्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं और प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से परिपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से भी पूरा सहयोग प्राप्त होता रहा है। हमने अनेक परियोजनाएँ केंद्रीय सहायता से विकसित की हैं। स्वदेश दर्शन में 'ट्रायबल टूरिज्म सर्किट' विकसित किया है। प्रशाद योजना में डोंगरगढ़ का कार्य अंतिम चरणों में है। इसके पूर्व जगदलपुर, चित्रकोट, भोरमदेव, सिरपुर, रतनपुर, मैनपाट, राजिम, मल्हार आदि स्थलों को केंद्रीय सहायता से विकसित किया है। इसमें राज्य बजट से भी कार्य कराया गया है। इन विकास कार्यों से और पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार से अब यहाँ पर्यटक आने लगे हैं और लगातार पर्यटकों की संख्या बढती जा रही है। आने वाले समय में राज्य में शक्तिपीठ स्थलों का विकास किया जायेगा। हम रोपवे एवं क्रूज पर्यटन के विकास के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं। नयी पर्यटन नीति पर कार्य चल रहा है एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु भी कार्यवाही चल रही है। हमने केंद्र की होमस्टे गाइडलाइन्स के आधार पर राज्य में 'होमस्टे एंड बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' गाइडलाइन्स तैयार कर जारी की है। इको टूरिज्म पॉलिसी, एडवेंचर गतिविधियों की गाइडलाइन्स, वाटर एक्टीविटी लाइसेंस हेतु गाइडलाइन्स बनाने की भी तैयारी चल रही है। राज्य में पर्यटन को और गति देने के लिये हमें पर्यटन मंत्रालय से नयी योजनाओं की स्वीकृति की अपेक्षाएँ हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में चयनित डेस्टीनेशंस बिलासपुर एवं जगदलपुर के लिये भारत सरकार के स्तर से कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है। प्रशाद योजना में सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ का कांसेप्ट प्लान जमा किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। अगले प्रस्तुतिकरण के अनुसार आगे भी नयी योजनाएँ तैयार हो रही हैं जिनके प्रस्ताव जल्द ही पर्यटन मंत्रालय को भेजे जायेंगे।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि निजी सहभागिता एवं निवेश तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा निर्मित किये

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.